

कांग्रेस ई.वी.एम. के मुद्दे पर मोदी सरकार से सीधी भिड़ंत के लिए तैयार

क्योंकि, लगातार हार के बाद ई.वी.एम. पर दोषारोपण ही प्रतिष्ठा बचाने का तरीका बचा है

-रेणु मिश्र-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 27 नवम्बर। कांग्रेस ने अन्ततः ई.वी.एम. के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ दो-दो हाथ करने का निर्णय ले लिया है।

चुनावों में बैलट पेपर के उपयोग को वापस लाने के मुद्दे पर गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को एक मंच पर लाने के लिए एक ठोस समन्वित रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि सभी एक आवाज में बोलें।

कांग्रेस के भीतर सभी विरोधी स्वयं को, जो कह रहे थे कि ई.वी.एम. ठीक है, चुप रहने और पार्टी लाइन पर चलने के लिए कहा गया है।

हरियाणा तथा महाराष्ट्र की करारी हार के बाद, ई.वी.एम. पर सारा दोष मढ़ने के अलावा, अपनी लाज रखने के लिए कांग्रेस नेतृत्व के पास और कुछ नहीं बचा है।

शरद पवार, अखिलेश यादव,

कांग्रेस के उन सभी नेताओं से मुंह बंद रखने के लिए कहा गया है जो मानते हैं कि ई.वी.एम. में कोई गड़बड़ नहीं है, इनमें राहुल गांधी भी हैं पर उन्हें भी समझा दिया गया है कि ई.वी.एम. पर दोषारोपण जरूरी है।

इंडिया गठबंधन के अन्य प्रमुख नेता, शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन पहले से ही ई.वी.एम. प्रणाली खत्म करने और बैलट पेपर से चुनाव कराने के हिमायती हैं, और अब इसमें ममता बनर्जी भी साथ आ गई हैं।

29 नवम्बर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ई.वी.एम. व्यवस्था खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किये जाने की संभावना है, इसके बाद यह प्रस्ताव इंडिया गठबंधन की बैठक में भी पारित किया जाएगा।

उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन तथा अन्य नेता पहले से ही ई.वी.एम. को हटाने के पक्ष में बोलते रहे हैं और अब ममता बनर्जी भी इन लोगों के साथ सुर मिलाने लगे हैं।

माना जा रहा है कि नवम्बर 29 की सी.डब्ल्यू.सी. (कांग्रेस वर्किंग कमेटी) की बैठक में कांग्रेस, ई.वी.एम. का उपयोग बंद करने की आवश्यकता पर

प्रस्ताव पास करेगी और शीघ्र ही इस प्रस्ताव को इण्डिया गठबंधन के सहयोगी दलों की मीटिंग में ले जाएगी, जिसके बाद विपक्ष इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगा। रणनीति तैयार की जा रही है और शीघ्र इसको कार्यान्वित किया जाएगा।

अभी तक कांग्रेस में ई.वी.एम. के समर्थन या विरोध को लेकर कोई स्पष्ट विजन नहीं था, दो-तीन तरह की बातें हो रही थीं।

सन् 2018 में, राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद, कांग्रेस का एक एजेण्डा था, ई.वी.एम. को हटाना, लेकिन, उसके बाद पार्टी नेतृत्व इस मुद्दे को लेकर ठंडा पड़ गया और उसे एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

लेकिन माना जा रहा है कि अब, सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच ई.वी.एम. का मुद्दा राजनीति की "सेंटर स्टेज" पर होगा तथा इसकी आवाज संसद और उसके बाहर सुनाई देगी।

प्रियंका गांधी आज शपथ लेंगी

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। केरल की वायनाड संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा गुरुवार को लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेंगी।

वाड़ा के साथ ही, महाराष्ट्र की नंदिड़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले रवींद्र चौहान भी लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे।

प्रियंका गांधी के साथ नंदिड़ से लोकसभा सदस्य बने रविन्द्र चौहान भी गुरुवार को सदस्यता की शपथ लेंगे।

इससे पहले, वायनाड के चुनाव अधिकारी ने बुधवार को श्रीमती वाड़ा को वायनाड संसदीय उपचुनाव का निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी उपस्थित रहे। वाड़ा ने वायनाड के लोगों का जबरदस्त समर्थन कर उन पर विश्वास करने के लिए आभार व्यक्त किया।

कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, आज होगा फैसला

आज हो रही एन.डी.ए. की बैठक में शाह के समक्ष एकनाथ शिंदे, अजित पवार, और फड़नवीस के बीच बातचीत होगी

-श्रीनंद झा-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 27 नवम्बर। गुरुवार को होने वाली नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एन.डी.ए.) की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का फैसला होगा।

एकनाथ शिंदे का गुट मुख्यमंत्री के चयन में बिहार मॉडल अपनाते पर जोर दे रहा है। इसलिए बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सम्बंध में कोई निर्णय नहीं हो सका। यह तय हुआ है कि गुरुवार को एन.डी.ए. की बैठक में अमित शाह के सामने महायुक्ति के तीनों नेता एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेन्द्र फड़नवीस बातचीत करेंगे।

मीटिंग में मुख्यमंत्री के पद के अलावा इससे सम्बंधित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी जैसे किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलेंगे और किस मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि एकनाथ शिंदे को

शिंदे समर्थक चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, पर शिंदे की पार्टी का कहना है कि बिहार मॉडल की तर्ज पर मुख्यमंत्री का फैसला होना चाहिए।

पर, आज शिंदे ने कुछ नरमी दिखाई और बताया कि उन्होंने प्र.मंत्री मोदी व गृहमंत्री शाह से मिलकर बात दिया है कि न तो वे और न ही उनकी पार्टी महाराष्ट्र सरकार के गठन में कोई अड़ंगा लगाएगी।

मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग जोर-शोर से उठ रही है पर बुधवार को खुद शिंदे ने समझौते के संकेत दिए और कहा कि न तो वे खुद और न ही उनकी पार्टी सरकार गठन में अड़चन पैदा करेगी। शिंदे ने कहा कि उन्होंने सरकार गठन का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ दिया।

शिंदे ने बुधवार को बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री

अमित शाह के साथ बात की है। उन्होंने कहा कि "मैंने उन्हें बताया है कि वे जो चाहे निर्णय लें हमारी पार्टी उसे स्वीकार करेगी और जिसे भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उसके प्रति कोई असंतोष नहीं रखेंगे।"

हालिया विधानसभा चुनावों में महायुक्ति को शानदार जीत मिली है, जिसमें भाजपा को 131, अजित पवार की एन.सी.पी. (नेशनलिस्ट कांग्रेस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष के हंगामे के कारण दूसरे दिन भी नहीं चली संसद

सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था

- जाल खंबाता -

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 27 नवम्बर। बुधवार को दूसरे दिन भी संसद नहीं चली, क्योंकि विपक्ष ने संसद के दोनों सदन में भारी हंगामा किया।

राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी स्थगन नोटिस टुकड़ा दिए। इनमें संयुक्त संसदीय समिति के गठन, मणिपुर तनाव और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा से सम्बंधित स्थगन प्रस्ताव भी शामिल थे। उन्होंने सबसे पहले राज्यसभा को सुबह आधे घंटे के लिए स्थगित किया और उसके बाद राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

प्रश्न काल के आरम्भ से ही विपक्षी दलों द्वारा हंगामा करने से लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला काफी क्षुब्ध नजर आए। सुबह उन्होंने सदन में कोई काम नहीं हुआ। विपक्षी दल गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे आरोपों पर संसद में चर्चा न कराये जाने का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर हिंसा व संभल

लोकसभा स्पीकर विपक्ष के रवैये से काफी क्षुब्ध नजर आए, लोकसभा में विपक्ष ने सुबह से ही विरोध और हंगामा शुरू कर दिया था।

इसके बाद पहले लोकसभा दोपहर तक फिर पूरा दिन के लिए स्थगित हो गई। स्पीकर ने विपक्ष के सभी स्थगन नोटिस अस्वीकार कर दिए।

राज्यसभा में भी यही माहौल देखा गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर तनाव, संभल दंगे और जे.जी.सी. की मांग संबंधित विपक्ष के सभी स्थगन नोटिस टुकड़ा दिए।

दिए हैं। मंत्रियों व सदस्यों के बयान के बाद, उन्होंने दिन भर के लिए सदन स्थगित कर दिया।

सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र का आरंभ हुआ तथा उस दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण सदन में कोई काम नहीं हुआ। विपक्षी दल गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे आरोपों पर संसद में चर्चा न कराये जाने का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर हिंसा व संभल

के दंगे पर भी विपक्ष चर्चा चाहता है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में रोड़ रोलर तरीकों पर चल रही है और विपक्ष की आवाज दबा रही है।

उन्होंने कहा कि गुरुवार को भी विपक्ष विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा। और जब तक सरकार उन मुद्दों पर चर्चा की अनुमति नहीं देती, जिन नोटिस जारी किए गए हैं, विपक्ष अपना विरोध जारी रखेगा।

'संविधान दिवस मना रहे हैं, बुजुर्गों का खयाल करें'

जयपुर, 27 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुजुर्ग लोगों को पेंशन सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से जुड़े मामले में कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि भले ही हम संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, जिससे उनसे जुड़े पेंशन

हाईकोर्ट ने कहा, 95 वर्षीय अनपढ़ विधवा के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बायोमेट्रिक नहीं होने के कारण बैंक खाता नहीं खुला व पेंशन नहीं मिली। राज्य सरकार दिशा निर्देश दे, तथा पेंशन दिलाये।

व अन्य मामलों में उनकी मदद हो सके। जबकि एक कल्याणकारी राज्य में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि ऐसे लोगों के मामलों के निस्तारण के लिए हेल्प सेंटर व पॉलिसी बनाई जाए, ताकि इनकी समय पर मदद हो सके। वहीं अदालत ने मामले में राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शाह की धमकी का असर, नरम पड़े शिंदे

अन्ततोगत्वा मजबूरी में ही सही पर शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर दावा छोड़ दिया है

-जाल खंबाता -

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 27 नवम्बर। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस धमकी के बाद कि अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भाजपा नेता देवेन्द्र फड़नवीस महाराष्ट्र सरकार का गठन कर लेंगे, शिव सेना नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए अपने दावे को वापस लेने के लिए बाध्य हो गए हैं।

शिंदे ने बुधवार को अपने निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के मुद्दे को लेकर भाजपा के निर्णय के विरुद्ध नहीं है और वो प्रधानमंत्री मोदी तथा अमित शाह के निर्णय को मानेंगे।

उन्होंने कहा, "मैं सरकार के गठन में बाधा नहीं हूँ तथा एन.डी.ए. (नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस) नेतृत्व का निर्णय मेरी शिव सेना को स्वीकार होगा।"

लेकिन वे गुरुवार को प्रधानमंत्री तथा अमित शाह का अन्तिम निर्देश प्राप्त करने के लिये, फड़नवीस तथा अजित

शिंदे ने कहा, वे सरकार के गठन में बाधा नहीं हैं, उन्हें भाजपा नेतृत्व का निर्णय स्वीकार होगा।

ज्ञातव्य है कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले ही कहा था कि भाजपा अजित पवार की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेगी। दोनों के पास पूर्ण बहुमत है उन्हें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद शिंदे को अंततः पीछे हटना पड़ा।

भाजपा सूत्रों ने कहा कि देवेन्द्र फड़नवीस के नेतृत्व में बन रही नई सरकार में शिंदे उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए हैं। अजित पवार ने पहले ही भाजपा का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है और वे उपमुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं।

पवार के साथ दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मोदी और शाह उनके साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़े हैं। शपथ ग्रहण समारोह रविवार को भुजबई में होना सम्भावित है। भाजपा सूत्रों ने यहाँ कहा कि एकनाथ शिंदे अजित पवार के साथ

उपमुख्यमंत्री के रूप में नई सरकार का हिस्सा बनने के लिये सहमत हो गये हैं। शपथ लेने वाले मंत्रिमण्डल में 20 मंत्री होंगे, जिनमें 10 भाजपा से, 6 शिंदे की शिव सेना से तथा 4 अजित पवार की एन.सी.पी. (नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी) से होंगे।

प्रिसिपल व दो शिक्षकों ने नाबालिग से गैंगरेप किया

मनेन्द्रगढ़, 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में एक स्कूल के प्रिंसिपल और दो शिक्षकों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की मदद करने के आरोप, वन विभाग के एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, आरोपियों की पहचान सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक रावेन्द्र सिंह कुशवाह के रूप में हुई है। अशोक कुमार कुशवाह और कुशल सिंह परिहार दोनों उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। बनवारी सिंह वन विभाग का कर्मचारी है।

लड़की के साथ कथित तौर पर दो बार बलात्कार किया गया। पहली घटना 15 नवंबर को हुई, जब लड़की को एक आरोपी के घर ले जाया गया और हेडमास्टर और दो शिक्षकों ने कथित तौर पर उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपी ने उसे घटना के बारे में किसी को न बताने की चेतावनी दी। दूसरी

छत्तीसगढ़ में आरोपी प्रिंसिपल व शिक्षकों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

आरोपी पढ़ाई में मार्गदर्शन देने के बहाने छात्रा को एक आरोपी के घर ले गये और गैंगरेप किया।

घटना 22 नवंबर की है। जब पीड़िता किराने का सामान खरीदने के लिए एक दुकान पर जा रही थी, तो आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर उसे बस स्टॉप के पास रोका और धमकी दी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, वह उसे अपनी बाइक पर वन विभाग के कर्मचारी के किराए के आवास पर ले गया, जहाँ फिर से उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया।

दूसरी घटना के बाद, लड़की ने अपने माता-पिता को बताया, जिन्होंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी पढ़ाई में मार्गदर्शन देने के बहाने लड़की के करीब आया, जो दूसरे स्कूल में पढ़ ती थी। पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

चारों आरोपियों पर बी.एन.एस. धारा 70(2) (नाबालिग से सामूहिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

झांसी कॉलेज अग्निकांड में तीन निलम्बित

लखनऊ, 27 नवंबर। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में नवजात बच्चों की मौत के मामले में हुई जांच के बाद कालेज के प्रधानाचार्य को हटा दिया गया है। जबकि कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को चार्जशीट दी गई एवं तीन अन्य को निलम्बित किया गया है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार

चार सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने कार्यवाही की।

को बताया कि अग्निकांड को लेकर गठित चार सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को यह कार्यवाई की गयी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक किंजल सिंह के नेतृत्व में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर दावा कर रही हैं ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने साफ कहा, तृणमूल रबर स्टम्प नहीं है जो कांग्रेस की हर बात माने

डाॅ. सतीश मिश्रा - राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 27 नवम्बर। पश्चिमी बंगाल में हाल ही में हुये विधान सभा चुनावों में हाल में हुई विजय से उत्साहित एवं प्रफुल्लित, टी.एम.सी. प्रमुख एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी दलों में अपनी श्रेष्ठता पर जोर देते हुये, राजनैतिक रूप से अपना सीना ठोक रही हैं ताकि इंडिया ब्लॉक उनके नियंत्रण में आ जाये।

हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई जबरदस्त पराजयों के बाद, इंडिया ब्लॉक में एक दरार के संकेत देते हुये, तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि टी.एम.सी. इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के निर्णयों के लिये रबर-स्टाम्प नहीं बनेगी। कथित भ्रष्टाचार पर संसद में चर्चा पर कांग्रेस के जोर के साथ मतभेद व्यक्त करते हुये, ममता बनर्जी के नेतृत्व

वाली पार्टी ने कहा कि पार्टी चाहती है कि संसद में काम-काज हो, जिससे पार्टी पश्चिम बंगाल की जनता के मुद्दों को संसद में उठा सके।

तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) के सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के रूख को स्वीकृति प्रदान कर दी है। बनर्जी ने जोर देते हुये कहा है कि टी.एम.सी. और कांग्रेस दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सदस्य हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, टी.एम.सी. की चुनावी सहयोगी पार्टी नहीं है तथा टी.एम.सी. कांग्रेस द्वारा लिये गये "इक्तरफा निर्णयों" को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है।

कांग्रेस और टी.एम.सी. ने लोकसभा चुनाव तथा हाल ही में हुये पश्चिम बंगाल के उपचुनाव अलग-अलग लड़े थे। टी.एम.सी. ने उपचुनाव की सभी छः सीटें जीत लीं हैं तथा

तृणमूल नेताओं ने कहा, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक घटक दल है पर प. बंगाल में कांग्रेस से हमारा गठबंधन नहीं है।

ममता बनर्जी का रूख आज तब और स्पष्ट हो गया जब उन्होंने भ्रष्टाचार पर बहस के कांग्रेस के रूख को टुकड़ा दिया और साफ कहा कि उनकी पार्टी सदन चलने के पक्ष में है और विपक्ष के विरोध का हिस्सा नहीं है।

पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ी है, इसलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर सीधा प्रहार करना शुरू कर दिया है।

लोकसभा चुनावों में भी 40 में से 29 सीटें जीत ली थीं। यह संख्या 2019 के विजेताओं की संख्या से ज्यादा थी, जबकि भाजपा ने राज्य में अपना पूरा जोर लगा दिया था।

एक टी.एम.सी. नेता ने कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार, जो विपक्ष के प्रमुख मुद्दों में से एक है, जिसके कारण संसद के दोनों सदन सोमवार से स्थगित चल रहे हैं, पर चर्चा तो चाहती है, लेकिन वह

यह भी नहीं चाहती कि यह मुद्दा पश्चिम बंगाल की जनता के मुद्दों के महत्व को कम कर दे।

उस नेता ने कहा, "पश्चिम बंगाल को फंड्स से वंचित कर दिया गया है, पूरे देश में कीमते बढ़ रही हैं तथा हम दुष्कर्म पीड़िताओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिये कानून लाने पर जोर दे रहे हैं। ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं, जिन्हें हम उठाना चाह रहे हैं। इसके लिये, हमारे लिये संसद का चलना जरूरी है।

केन्द्र में इंडिया गठबंधन की सदस्य होने के बावजूद, टी.एम.सी. और कांग्रेस के बीच का रिश्ता बड़ा असहज है तथा ऐसी भी अटकलें हैं कि लोकसभा चुनावों से पहले, यह क्षेत्रीय दल विपक्षी गठबंधन से अलग हो जाये। हालांकि ममता बनर्जी तथा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा वरिष्ठ नेता

राहुल गांधी शामिल हैं, के बयानों द्वारा दोनों दलों के बीच की दरारों को ढकने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन वे बार-बार दिखाई देने लगती हैं।

अक्टूबर में, हरियाणा में हुई कांग्रेस की अप्रत्याशित हार के बाद, तृणमूल कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक के प्रमुख दल कांग्रेस पर प्रहार करने में बहुत तत्परता दिखाई तथा कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस को "अहंकार" हो गया है तथा वह उन राज्यों, जहाँ वह स्वयं को मजबूत मानती है, में क्षेत्रीय दलों के साथ समायोजन नहीं करती है।

तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने कहा था, "इस प्रवृत्ति से चुनावों में नुकसान उठाना पड़ता है- 'अगर हम यह महसूस करते हैं कि हम जीत रहे हैं, तो हम क्षेत्रीय पार्टी के साथ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

नारी सब कुछ सह सकती है, दारुण से दारुण दुःख, बड़े से बड़ा संकट। नहीं सह सकती तो अपनी उमंगों का कुचला जाना। -प्रेमचंद

संदर्भ महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव परिणाम महिला मतदाताओं की मुखरता से बदल रही चुनावी नतीजों की तस्वीर

महाराष्ट्र विधान सभा के चुनावों ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी नतीजों को बदलने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों में महिलाओं के 6 प्रतिशत अधिक मतदान ने चुनावी परिणामों को ही पूरी तरह से बदल कर रखा है। इसी साल की शुरुआत में हुए लोकसभा के चुनाव परिणामों से महाराष्ट्र में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका रही। मध्यप्रदेश से निकली लाइली बहना महाराष्ट्र तक आते आते माझी लाइली बहना योजना ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसी साल लागू करने और चुनाव से पहले ही तीन किशतें लक्षित महिलाओं के खातों में जाने से पूरा माहौल ही बदल गया। योजना शुरू करने पर विचार में विरोध किया और यहां तक कि कोर्ट में जनहित याचिकाएं लाई गईं पर कोर्ट द्वारा योजना को सही ठहराने और सीधे खाते में पैसे आने से महिलाओं में सरकार के प्रति विश्वास जाग्य वही महाअघाडी गठबंधन महिलाओं से जुड़ी इस योजना को समझने में ही देरी कर दी और भले ही बाद में चुनाव घोषणा पत्र या यों कहे कि चुनावी वादों में अधिक पैसा देने का वादा भी किया पर महिलाओं का विश्वास नहीं जीत पाए। परिणाम सामने हैं जो मिल रहा है वह बढ़कर मिलेगा इस पर महिलाओं ने अधिक विश्वास जताया। सही मायने में देखा जाए तो महिला शक्ति गेम चेंजर बन कर सामने आई। कहा तो यहां तक जाने लगा है कि महिलाएं जिनके साथ है सत्ता भी उनके हाथ ही लगेगी।

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में चुनावों में महिलाओं की बढ़ती सक्रिय भागीदारी तारीफे काबिल है। गत चुनावों चाहे वे लोकसभा के हों या राज्यों की विधानसभाओं के देश की महिला वोटर्स ने नई सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मजे की बात यह भी है कि चुनाव में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं ने अधिक मुखर होकर मतदान किया है। अब तो यह माना जाने लगा है कि देश के एक दर्जन के करीब राज्यों में महिलाओं के वोट ही नई सरकार के गठन में बड़ी भूमिका निभाने लगे हैं। तस्वीर का सकारात्मक पक्ष यह भी है कि मतदान ही नहीं चुनावों में सक्रियता से हिस्सा लेने और चुनावों में उम्मीदवारी जताने में भी महिलाएं आगे आई हैं। देश के पहले और दूसरे लोकसभा के आमचुनावों में जहां 22 महिला सांसद चुन कर आई थी वहीं गत 2024 के आमचुनाव में 74 महिला सांसद चुन कर आईं। हालांकि आधी आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नए नए सबबाग दिखाने के बावजूद टिकट वितरण के समय महिलाओं की हिस्सेदारी कम ही रह जाती है। अनुभव तो यही बताता है कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा आधी तो दूर की बात एक तिहाई सीटों

पर भी महिलाओं को टिकट नहीं दिए जाते हैं। इस बार महाराष्ट्र चुनावों में 50 महिलाओं को टिकट दिए गए और 21 महिलाएं चुनाव जीत कर विधायक बनी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि गांव या शहर महिलाएं अब घर की चार दीवारी में कैद रहने वाली या पुरुष के कहे अनुसार मतदान करने वाली नहीं रही हैं। पुरुषों के हां में हां मिलाने वाली स्थिति से बहुत बाहर आ चुकी है आज देश की महिलाएं संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में महिलाएं सक्रियता से हिस्सा लेने लगी हैं। चुनावों में उम्मीदवारी भी जताती है तो चुनाव कैंपेन के दौरान अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराती हैं। दूसरी और मतदान में भी आगे आकर हिस्सा लेने लगी हैं। देखा जाए तो महिलाओं ने जिस दल पर अधिक भरोसा जताया था यों कहे कि जिस दल को अधिक मत दिए उसी दल की सरकार बनी। मजे की बात यह है कि अब सभी राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के हर संभव प्रयास में जुटे हैं। यही कारण है कि महिलाओं को लुभाने वाली योजनाएं और कार्यक्रम ना केवल पोषित किये जा रहे हैं अपितु राजनीतिक दलों के आने वाले चुनाव घोषणा पत्रों में महिला मतदाताओं को लुभाने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। क्योंकि एक बात साफ हो चुकी है कि आज की महिला स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है और उसको दबाव या अन्य तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता। कम से कम चुनावों के परिणाम तो इसी और इंगित कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि माझी लाइली बहना योजना में 2.50 लाख आय वाली 18 से 60 साल की महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया। इससे यह साफ हो जाता है कि यह वर्ग कमजोर आर्थिक आय वाली महिलाओं का है। यहां साफ हो जाता है कि महिलाओं का यह वर्ग वो है जिसके बारे में यह माना जाता है कि इस वर्ग में महिलाएं पुरुषों के निर्णयों पर अधिक निर्भर होती हैं पर महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों के चुनावी नतीजों से यह साफ हो गया है कि महिलाएं पुरुषों की हां में जो न मिलकर स्वयं निर्णय लेने लगी हैं और उसीसे ताजा नतीजें रबक कराते हैं।

खैर यह अलग बात है, पर यह साफ हो चुका है कि देश के लोकतंत्र के इस महापर्व में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाने जा रही हैं। अब महिला मतदाताओं को कमतर नहीं आंका जा सकता। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी इसे सशुभ संकेत माना जा सकता है। इसे देश और लोकतंत्र दोनों के लिए ही सकारात्मक प्रयास कहा जा सकता है तो दूसरी ओर दुनिया के देशों के लिए भी भारत की महिलाएं एक मिसाल बन कर सामने आ रही हैं। इसमें कोई अविशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि भविष्य के चुनावों में भी राजनीतिक दलों को सत्ता का स्वाद चखना है तो निगाहें महिला मतदाताओं की ओर रखनी ही होगी।

-अतिथि सम्पादक,
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल गुरुवार 28 नवम्बर, 2024

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत् 2081, चित्रा नक्षत्र प्रातः 7:36 तक, सौभाग्य योग सायं 4:01 तक, गर करण सायं 7:32 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-तुला, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरु-वृष, शुक्र-धनु, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज प्रदीप व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:19 तक, चर 10:56 से 12:15 तक, लाभ-अमृत 12:15 से 2:52 तक, शुभ 4:10 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:00, सूर्यास्त 5:29

मेघ

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मार्गलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिवर्तनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

वृष

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

मिथुन

व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आज महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

कर्क

घर/परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। परिवार में आपसी अनबन हो सकती है। स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

सिंह

मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। परिवर्तनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्यों बन्ने लगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

तुला

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक

घर-परिवार के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज अमंगल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

धनु

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

मकर

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगे। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज बने कार्य विगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। यात्रा में परेशान हो सकती है।

उच्च शिक्षा - स्ववित्तीय पोषित शिक्षकों की व्यथा



प्रो. अशोक कुमार

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यक्तिगत के समग्र विकास एवं राष्ट्र के नागरिक तैयार करने में किसी भी देश में शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षा संरचना, पाठ्यक्रम-पाठ्यचर्या गुणवत्ता, सुलभता तथा देश की संस्कृति के अनुरूप शिक्षा आदि विषयों पर सार्वजनिक चर्चा होती रही है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा किसी भी समाज के विकास का आधार होती है और इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल ज्ञान देते हैं बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व का विकास भी करते हैं। जब पूरी दुनिया ने विद्यालय की कल्पना नहीं की थी, उस समय हमारे यहाँ विश्वस्तरीय नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षिला विश्वविद्यालय, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करते थे। परंतु वर्तमान में शिक्षा-व्यवस्था की विसंगतियाँ कहीं-न-कहीं बहुत कचोटती हैं।

भारत की स्वतंत्रता के बाद, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हुआ और इसी दौरान स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों का उदय हुआ। इन संस्थानों ने उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 और 90 के दशक में निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों के कारण स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। सरकारी महाविद्यालयों में सीमित सीटों के कारण, सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता था। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप कई नए स्ववित्तीय पोषित शिक्षण संस्थान स्थापित हुए। स्ववित्तीय पोषित शिक्षण संस्थान वे संस्थाएँ होते हैं जो सरकार से सीधी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करते हैं। ये संस्थाएँ अपने खर्चों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे कि फीस, दान, और अन्य आय के माध्यम से धन जुटाते हैं। 21वीं सदी में उच्च शिक्षा के प्रति बढ़ती मांग के कारण स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में और वृद्धि हुई। शिक्षा में निजीकरण के उदय के साथ इस विचार ने महत्वपूर्ण गति प्राप्त की, विशेष रूप से भारत में, जहाँ सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों को स्व-वित्तपोषित आधार पर संचालित करने की अनुमति देनी शुरू कर दी, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ था कि वे संचालकों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संचालन धन के बजाय छात्र शिक्षण पर निर्भर रहेंगे। स्ववित्तीय पोषित शिक्षण संस्थानों के विभिन्न प्रकार हैं जैसे निजी स्ववित्तपोषित: ये शिक्षण संस्थान पूर्ण तरह से निजी धन पर चलते हैं। वे अपनी स्वयं की पाठ्यक्रम,

फीस संरचना और प्रवेश मानदंड निर्धारित करते हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय: ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और उन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। वे स्वायत्त होते हैं और अपनी नीतियाँ स्वयं बना सकते हैं। कॉलेज: ये संस्थान विश्वविद्यालयों से संबद्ध होते हैं और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। संस्थान: ये संस्थान किसी विशेष विषय या क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। उदाहरण के लिए, मेडिकल संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रबंधन संस्थान आदि। इन स्ववित्तीय पोषित शिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की पेशकश शुरू की, जिससे छात्रों के पास अधिक विकल्प उपलब्ध हुए। सरकार की नई शिक्षा नीतियों ने निजी क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चों जनसंख्या और शिक्षा के प्रति जागरूकता: बढ़ती जनसंख्या और शिक्षा के प्रति जागरूकता के कारण उच्च शिक्षा की मांग में वृद्धि हुई।

वर्तमान में (2021-22) की रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत 1168 विश्वविद्यालयों में से 685 सरकारी प्रबंधन वाले हैं। 10 निजी डीम्ड और 473 निजी हैं। पंजीकृत कॉलेज 45473 हैं। महाविद्यालयों में से 21.5 प्रतिशत कॉलेज सरकारी कॉलेज हैं, 13.2 प्रतिशत निजी (सहायता प्राप्त) हैं और 65.3 निजी (गैर-सहायता प्राप्त) हैं। सरकारी कॉलेज कुल महाविद्यालयों का 21.5 प्रतिशत हिस्सा है, 13.3 प्रतिशत निजी (सहायता प्राप्त) कॉलेज हैं, है, जबकि 65.2 प्रतिशत निजी (गैर-सहायता प्राप्त) कॉलेज हैं, जिनमें छात्रों का कुल नामांकन का केवल 44.6 प्रतिशत है।

आज एक बहुत ही मुख्य विषय है कि क्या शिक्षा के लिए जो शिक्षण संस्थान खुले जा रहे हैं विशेष तौर से निजी क्षेत्रों में क्या यह शिक्षा के लिए खुले जा रहे हैं या व्यवसाय के लिए खोले जा रहे हैं यह बहुत ही गंभीर विषय है इस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। निजी कॉलेज क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें तेजी से बढ़ने दिया गया है। ऐसे अधिकांश संस्थान वास्तव में शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में रियल एस्टेट रैकेट हैं। उनमें से अधिकांश राजनेताओं और बिल्डरों द्वारा नियंत्रित हैं। किसी बड़े शहर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता नष्ट खिलानियों के लिए एक बड़ी बाधा की तरह लगती है, जिनके पास बहुत अधिक धन या राजनीतिक संबंध हैं। निजी स्ववित्तपोषित शिक्षण संस्थानों के स्थापित करने में यह प्रावधान है कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी नियुक्तियाँ यूजीसी मानदंडों: के अनुसार की जाएंगी लेकिन वेतनमान सरकार द्वारा विनियमित की जाएंगे। स्व-वित्तपोषण संस्थानों, मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में भी शिक्षकों के वेतन को लेकर लंबे समय से असंतोष व्याप्त रहा है। इन संस्थानों में शिक्षकों को अक्सर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में काफी कम वेतन दिया जाता है। सेल्फ फाइनेंस डेब्री महाविद्यालयों में शिक्षकों का मासिक वेतन 5-5 हजार रुपये है (मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़ कर

6,549 फैंकल्टी के पद खाली हैं। उनमें से अधिकांश दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, जहाँ 900 रिक्त पद हैं, इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 622 पद, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 532 पद और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 498 पद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 326 रिक्त संकाय पद हैं। विकसित देश में शिक्षा का भविष्य अस्थायी शिक्षकों के सहारे पर निर्भर है जिनको विभिन्न नाम से जाना जाता है। अस्थायी, एडहॉक, सविदा, पार्टटाइमर, अतिथि, मानद, विजिटिंग, आवश्यकता आधारित, एमओयू प्रोफेसर, शोधविद्वान, ऑनलाइन अतिथि संकाय, स्व अस्थायी। विशेष: प्रतिस्थापन, सत्रिय, सहायक शिक्षक। शिक्षा का विकास सिर्फ कॉलेज खोलने से नहीं होता! सरकार ने अब तक समय में नए कॉलेज खोलकर एक कॉलेजियन स्थापित किया है लेकिन क्या स्थिति चाकई ऐसी है कि उस पर गर्व किया जाए? क्या केवल कॉलेज विश्वविद्यालय एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, अमृता विश्व विद्यापीठम, अमृता विश्व विद्यापीठम, वीआईटी यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ओपी ज़िंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस, व्हेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी), एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लोक विश्वविद्यालयों में सुवित्तपोषित डिब्री महाविद्यालयों में बीएससी, बीकॉम का शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित सिर्फ 5000 - 6000 रूपए वार्षिक है। छात्रों द्वारा ली गई शिक्षण फीस पूरी तरह से शिक्षकों के वेतन पर खर्च नहीं होती है। शिक्षकों की भर्ती के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है, जिसका फायदा उठाकर संस्थान कम वेतन पर शिक्षकों की भर्ती करते हैं। भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में भी स्ववित्तीय पोषित संस्थानों का तेजी से विस्तार हुआ है। ये संस्थान आमतौर पर उच्च फीस लेते हैं और दावा करते हैं कि वे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि, इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को भी अक्सर वेतन के मामले में शोषण का सामना करना पड़ता है। यह समस्या न केवल शिक्षकों के लिए चिंता का विषय है बल्कि छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के लिए भी खतरा है। समस्या का मूल कारण लागू वसूली का दबाव है। स्ववित्तीय पोषित संस्थानों पर उच्च लागत वसूली का दबाव होता है। वे अपनी बुनियादी सुविधाओं, कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक फीस वसूल करते हैं। इस दबाव में वे अक्सर शिक्षकों के वेतन पर कंजूसी करते हैं। यही नहीं बहुत से महाविद्यालयों में अनुमोदित शिक्षकों की जगह किसी और से काम लिया जाता है। शिक्षक-प्राचार्य नियमित तौर पर उपस्थित नहीं रहते और पढ़ाई की गुणवत्ता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। इक्का-दुक्का महाविद्यालयों को छोड़कर ज्यादातर की यही स्थिति है। स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की आय का एकमात्र जरिया फीस ही है इसलिए इसे बढ़ाने के अलावा उच्च शिक्षा की रक्षा और दिशा सुधारने का दूसरा कोई विकल्प

नहीं है। इन शिक्षकों से ज्यादा एक दिन की दिहाड़ी 600 रुपये तो मजदूर पाता है। अगर औसत निकाला जाए तो अधिकतम वेतन 10 से 12 हजार रुपये तक है। ये स्थिति तब है जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमित शिक्षकों के जितना वेतन इन्हें भी देने को कहती है। उच्च शिक्षा में इतिहास, हिंदी जैसे विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन तो और भी कम है। इन विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को पांच-पांच हजार रुपये तक का वेतन दिया जाता है। इस पर भी साल में सिर्फ 11 महीनों का वेतन मिलता है। यह समस्या कई कारणों से जटिल है। ये संस्थान सरकार से स्वायत्त होते हैं, जिसके कारण वे अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। इन संस्थानों में फीस संकलन में बहुत अंतर है। भारत में कई निजी विश्वविद्यालय हैं जो लाखों (5-30 लाख तक) में टयूशन फीस के साथ स्नातक कार्यक्रम प्रदान करते हैं उदाहरण के लिए मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, अमृता विश्व विद्यापीठम, अमृता विश्व विद्यापीठम, वीआईटी यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ओपी ज़िंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस, व्हेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी), एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लोक विश्वविद्यालयों में सुवित्तपोषित डिब्री महाविद्यालयों में बीएससी, बीकॉम का शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित सिर्फ 5000 - 6000 रूपए वार्षिक है। छात्रों द्वारा ली गई शिक्षण फीस पूरी तरह से शिक्षकों के वेतन पर खर्च नहीं होती है। शिक्षकों की भर्ती के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है, जिसका फायदा उठाकर संस्थान कम वेतन पर शिक्षकों की भर्ती करते हैं। भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में भी स्ववित्तीय पोषित संस्थानों का तेजी से विस्तार हुआ है। ये संस्थान आमतौर पर उच्च फीस लेते हैं और दावा करते हैं कि वे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि, इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को भी अक्सर वेतन के मामले में शोषण का सामना करना पड़ता है। यह समस्या न केवल शिक्षकों के लिए चिंता का विषय है बल्कि छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के लिए भी खतरा है। समस्या का मूल कारण लागू वसूली का दबाव है। स्ववित्तीय पोषित संस्थानों पर उच्च लागत वसूली का दबाव होता है। वे अपनी बुनियादी सुविधाओं, कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक फीस वसूल करते हैं। इस दबाव में वे अक्सर शिक्षकों के वेतन पर कंजूसी करते हैं। यही नहीं बहुत से महाविद्यालयों में अनुमोदित शिक्षकों की जगह किसी और से काम लिया जाता है। शिक्षक-प्राचार्य नियमित तौर पर उपस्थित नहीं रहते और पढ़ाई की गुणवत्ता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। इक्का-दुक्का महाविद्यालयों को छोड़कर ज्यादातर की यही स्थिति है। स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की आय का एकमात्र जरिया फीस ही है इसलिए इसे बढ़ाने के अलावा उच्च शिक्षा की रक्षा और दिशा सुधारने का दूसरा कोई विकल्प

नहीं है। कई निजी महाविद्यालयों का तर्क है कि सुदूर टामीण क्षेत्रों में कॉलेज की आय उतनी नहीं हो पाती है। वही यूजीसी की योग्यता के शिक्षक नहीं मिल पाते। संस्थान कम वेतन पर शिक्षकों की भर्ती करते हैं। कम वेतन के कारण योग्य शिक्षक इन संस्थानों में काम करने से हिचकिचाते हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। कम वेतन और असुरक्षित कार्य वातावरण के कारण योग्य शिक्षक इन संस्थानों को छोड़कर अन्य जगहों पर रोजगार की तलाश करते हैं। योग्य शिक्षकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आती है। छात्रों को कम गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलती है और उन्हें उच्च फीस देनी पड़ती है। कम गुणवत्ता वाले शिक्षक, डॉक्टर और इंजीनियरों का उत्पादन होने से समाज को नुकसान होता है। इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को अक्सर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों की तरह सुरक्षा और अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वेतन, कार्यकाल और पेंशनिक के मामले में वे संस्थान प्रबंधन के दया पर निर्भर रहते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने अपने परिसर के स्ववित्तपोषित शिक्षकों को एक अच्छा वेतन एवं अन्य सुविधाओं देने की मांग को स्वीकार कर लिया है लेकिन विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कई संस्थान शिक्षकों पर विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगाते हैं जैसे कि अनुपस्थिति के लिए जुर्माना, लक्ष्य पूरे नहीं करने पर वेतन काटा जाना आदि। इसको लेकर कई बार विभिन्न प्रदेशों में सरकार तक शिकायतें की गईं। लेकिन, कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि सूत्रों के अनुसार ज्यादातर शिक्षण संस्थान नेता, मंत्री, विधायक और अधिकारियों के संबंध में या उनका इन संस्थानों से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। ऐसे में वह भी इनमें बदलाव नहीं चाहते हैं।

स्ववित्तीय पोषित डिब्री महाविद्यालय, मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में शिक्षकों के वेतन की समस्या के समाधान के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। सरकार को इन संस्थानों में शिक्षकों के वेतन को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। संस्थानों को अपने विधायक शिक्षकों को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि शिक्षक यह जान सकें कि संस्थान कितना मुनाफा कमा रहा है और शिक्षकों के वेतन पर कितना खर्च हो रहा है। संस्थानों को अपनी वित्तीय स्थिति और फीस संरचना के बारे में पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए। शिक्षकों को कर्मचारी संघों का गठन करके अपनी आवाज को मजबूत बनाना चाहिए। शिक्षकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें। छात्रों को भी इस मुद्दे के प्रति जागरूक होना चाहिए और शिक्षकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने चाहिए। सरकार, संस्थान, शिक्षक और छात्र सभी को इस समस्या के समाधान के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

- प्रो. अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय

“बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान को राजस्थान महिला कल्याण मण्डल का समर्थन

अजमेर (कांस)। भारत सरकार की ओर से नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत के बाद जिला प्रशासन ने राजस्थान महिला कल्याण मण्डल के सहयोग से रैलियों व शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अजमेर में हुए समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़ एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई के सहायक निदेशक संजय सांबलानी ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं एवं पदाधिकारियों को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाई, साथ ही संस्था मुख्यालय चाँचियावास में संयुक्त निदेशक अनुराग सक्सेना, अतिरिक्त निदेशक वैष्णव शर्मा, लेखाधिकारी नेमीचन्द्र तूरुण, सागर कॉलेज के इन्चार्ज डॉ. भवमान सहाय शर्मा की उपस्थिति में उपनिदेशक नानुलाल प्रजापति ने कॉलेज के छात्र-छात्राओं सहित स्टाफ को बाल विवाह मुक्त अजमेर के लिए शपथ दिलाते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी। राजस्थान महिला कल्याण मण्डल बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे 250 से भी ज्यादा गैरसरकारी संगठनों के देशव्यापी गठबंधन ‘वस्तु राइट्स फॉर चिल्ड्रेन्स’ का सहयोगी संगठन है जो कि राजस्थान के 6 जिलों में बाल विवाह की रोकथाम एवं जागरूकता के लिए पिछले 3 वर्ष से कार्य कर रहा है। भारत सरकार के नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के उद्घाटन के मौके पर संस्था ने अपने कार्यक्रम के अजमेर, नागौर, बीकानेर, चुरू, झुन्झुनू, तथा डीडवाना-कुचामन जिलों जागरूकता रैलियों का आयोजन किया

और लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। संस्था टीम ने जिले के 50 से अधिक गाँवों में स्कूली बच्चों, महिलाओं और पंचायत प्रतिनिधियों व अन्य को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। जिले में जगह-जगह हुए कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, बाल विवाह निषेध अधिकारी (सोएपीओ) के अलावा बाल विवाह पीड़िताओं ने भी भागीदारी की और बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली। यह कार्यक्रम देश से बाल विवाह के खत्म के लिए भारत सरकार का बाल विवाह मुक्त भारत के आव्हान के समर्थन में किया गया, जिसका उद्घाटन 27 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अनूपम देवी ने किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पंचायतों और स्कूलों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही शपथ लेने वालीं की संख्या 25 करोड़ तक पहुँच जाएगी। इस मौके पर बाल विवाहों की सूचना व शिक्षागत के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल भी शुरू किया गया। इस राष्ट्रीय अभियान और जमीन पर इसके असर की चर्चा करते हुए संस्था के निदेशक राकेश कुमार कोशिक ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाल विवाह के खत्म के लिए महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया अभियान इस बात का सबूत है कि सरकार इस सामाजिक बुराई की गंभीरता से अवगत है। अभियान की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने में संस्था टीम के दीपक जोरम, सतार मोहम्मद, ज्योति मण्डवतिया, योगिता गौड़ ने सहयोग किया।

कोटा के प्रत्यक्ष ने सबसे कम उम्र के योग टीचर का विश्व रिकॉर्ड बनाया



कोटा में रहने वाले प्रत्यक्ष ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है।

कोटा, (निर्स) जिस उम्र में बच्चों को योग के नाम भी नहीं आते उस उम्र का एक योग टीचर कोटा में रहता है। वह कई बच्चों और बड़ी उम्र के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। इस योग टीचर के नाम अब विश्व रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। यह उपलब्धि उन्हें अक्टूबर 2024 में ही मिली है। जिसके बाद प्रत्यक्ष ने विश्व के सबसे छोटे (कम उम्र) के योग टीचर के रूप में रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पूरी प्रक्रिया के बाद सर्टिफिकेट दिया है। इस सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड के लिए उन्होंने लंबी मेहनत की है।

प्रत्यक्ष कोरखेड़ा स्थित देवाशीष सिटी में अपने परिवार के साथ रहते हैं और यह सबकुछ उन्होंने अपनी मां दीक्षा विजय से ही सीखा है। इसके बाद प्रोफेशनल योग क्लास लिए और सिखाने लग गए हैं। प्रत्यक्ष के पिता गौरव विजय का कहना है कि सबसे कम उम्र के योगा टीचर बनने यह रिकॉर्ड उनके बेटे ने 6 साल की उम्र में ही बना लिया जबकि 4 साल की उम्र से वह योग सीखने लग गया था, 5 साल की उम्र में सिखाने भी लग गया था। फिलहाल, प्रत्यक्ष की उम्र 7 साल है। रिकॉर्ड के लिए उन्होंने बीते साल अप्रैल किया था। इससे पहले

यह रिकॉर्ड दुबई की एक लड़की के नाम था। वह साढ़े सात साल की थी। प्रत्यक्ष का कहना है कि बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रहना चाहिए वह खुद स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं। अपनी मां और पिता के फोन को नहीं छूते हैं। केवल बात करने के लिए ही फोन लेते हैं। अन्य बच्चों की तरह गैस और कार्टून का शौक उन्हें नहीं है। कुछ देर टेलीविजन जरूर देखते हैं। सबसे छोटे योग गुरु का खिताब लेने के बाद उनकी इच्छा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें। साथ ही जंक फूड से बच्चों को दूर रहने की सलाह देते हैं।

सार-समाचार

विद्यालयों का निरीक्षण किया

पाटन (निर्स)। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ पाटन व जिला मुख्यालय सीकर के तत्वावधान में आयोजित सघन निरीक्षण संघ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व प्रभारी कमिश्नर सत्य प्रकाश टेलर, प्रभारी कमिश्नर गाइड श्रीमती निर्मला देवी के नेतृत्व में स्थानीय संघ के विभिन्न विद्यालयों में सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोटामनी, नियुक्ति पत्र, नया रजिस्ट्रेशन इत्यादि की सूचना एकत्रित की गई। जिला प्रधान बाबूलाल गुर्जर सहायक जिला कमिश्नर ओम प्रकाश चौधरी व सहायक जिला कमिश्नर जयराम गुर्जर ने डाबला, बिहार, बिहारीपुर का सघन निरीक्षण किया। जिला कमिश्नर कमल कुमार लूनीवाल व स्थानीय संघ सचिव महेश कुमार योगी ने रायपुर पाटन, रैयाका बास, घासीपुर, कोला की नांगल व फागनवास का निरीक्षण किया। प्रकाश चंद मीणा सहायक जिला कमिश्नर व सहायक सचिव सीताराम गुर्जर ने बोपिया, बाबुलाल शारदा ने हसामपुर सहित अनेकों विद्यालयों का निरीक्षण किया। सहायक जिला कमिश्नर, अमर सिंह मीणा व कोषाध्यक्ष- धनंजय जी ने रामपुरा बेगा की नांगल दलपतपुरा आदि विद्यालयों का निरीक्षण किया। हजारि लाल देहरान ने डूंगा की नांगल व सोहनपुर का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण अभियान 28 नवंबर तक चलेगा। जिसमें स्काउट गतिविधियों में सक्रियता प्रदान करने व बच्चों का सर्वांगीण विकास हो एवं आगे बढ़े इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में जाकर के उनका निरीक्षण किया गया और स्काउट गतिविधियों से जोड़ने के लिए उनको मानसिक रूप से तैयार किया गया।

‘राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्र निर्माण एवं चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान’

सीकर, (निर्स)। राजकीय विज्ञान महाविद्यालय सीकर में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में संभाग स्तरीय (सीकर, झुंझून एवं अलवर) की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. डी.डी. गुडेचरिया ने की। कार्यक्रम दो सत्रों में आयोजित किया गया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि डॉ. ओमप्रकाश बैक्वा, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, डॉ. अनिल कुमार राय कुलपति, मुख्य वक्ता डॉ. के.के. कुमावत, कार्यशाला कॉर्डिनेटर विशिष्ट अतिथि रहे। द्वितीय समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में रतन कुमार अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर, डॉ. प्रियंका अमन एसोशियेट प्रोफेसर एस.के. मेडिकल कॉलेज, सीकर मुख्य वक्ता रहे। मंच संचालन के दायित्व का निर्वहन डॉ.रामदेव सिंह भामू व डॉ. चेतन कुमार जोशी ने किया। सभी वक्ताओं ने राष्ट्र निर्माण, समाज से विद्यार्थियों को जोड़ना, व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास, चरित्र निर्माण, कार्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी, परोपकार के भाव से सेवा भावना जैसे विषयों पर सारगर्भित व्याख्यान देकर प्रतिभागीयों का मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार खोड्डा, एनसीसी अधिकारी डॉ. सुभाष गौरा के नेतृत्व में एनसीसी केडेट्स और स्वयं सेवकों का कार्य सवहनीय रहा। कार्यक्रम के अंत में आयोजन सचिव डॉ. महेंद्र कुमार ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

डॉ. अम्बेडकर को याद किया

रतनगढ़ (निर्स)संविधान दिवस के उपलक्ष पर राजस्थान शिक्षक संघ (अंबेडकर) ब्लॉक रतनगढ़ द्वारा राजकीय चिकित्सालय के सामने स्थित बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के स्टेच्यू पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया गया और डॉ अंबेडकर के जय जकारों से परिसर को गुंजायमान कर दिया गया। इस मौके पर संगठन के जिलाध्यक्ष मास्टर शिवाराम मेघवाल ने संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का आ न किया। जिला पदाधिकारी शिवकुमार गाडगिल ने बताया कि बाबा साहेब थे तब हम है और उनके कृत्यों को भुलाया नहीं जा सकता। प्रदेश पदाधिकारी राकेश नायक ने संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया और संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई। संघटन के ब्लॉक सभाध्यक्ष वीरेंद्र जायसवाल ने पधार्य हुए सभी शिक्षक साथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर प्रदेश पदाधिकारी राकेश नायक के साथ जिला पदाधिकारी शिवकुमार गाडगिल, ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र नायक, ब्लॉक मंत्री अनिल कंवल, ब्लॉक सभाध्यक्ष वीरेंद्र जायसवाल, ब्लॉक कोषाध्यक्ष भंवरलाल सावा, प्रवक्ता अरुण जाड़ा, महिला मंत्री रजनी आनंद और मीना बारुपाल, उपसभाध्यक्ष परमेस्वरलाल नवल, पशु चिकित्सक डॉ. हुणताराम मीणा, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य जेपी भाटी सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे।

165 मरीजों की मोतियाबिंद कर जांच हुई

रतनगढ़ (निर्स)। रतनगढ़ माहेश्वरी सभा ट्रस्ट जालान सेवा ट्रस्ट ,शंकरा आई हॉस्पिटल व जिला अंधता निवारण समिति, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में नि:शुल्क मोतियाबिंद जांच व नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन बुधवार को माहेश्वरी भवन में हुआ। ट्रस्टी व शिविर प्रभारी नरेंद्र झंवर ने बताया कि शिविर में 165 मरीजों की मोतियाबिंद जांच कर 67 मरीजों का चयन नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के लिए एकत्रित गया। चयनित रोगियों को ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाया गया। वहां उनका ऑपरेशन गुफवार को आधुनिक तकनीक द्वारा बिना टांके का किया जाएगा। शिविर शुरू होने से पूरे भगवाना शंकर की प्रतिभा में प्रज्ज्वलित खण्डेवाल, रतनगढ़ शहर की आशा सहयोगिनी बहानों ने दीप प्रज्ज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। माहेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्ष मंजू लडा, सरिता चांदक, मंजू पेशवाल,चन्दा सोनी,एडवोकेट पूर्णिमा लडा ने आभूतक अतिथियों का अभिन्दन किया। शिविर में शंकरा आई हॉस्पिटल की टीम, माहेश्वरी समाज के महेश जाजू,एडवोकेट रजनीकांत सोनी, महावीर रामपटिया, पूर्णमल कम्मा, वासुदेव चाकलान, गोरशंकर जालान आदि ने अपनी सेवाएं दी।

सी.एच.सी. में कैंसर की स्क्रीनिंग हुई

सीकर (निर्स)।चिकित्सा विभाग की ओर से बुधवार रिंगस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जयपुर से आई मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग वैन की टीम ने रोगियों की कैंसर की स्क्रीनिंग की। साथ ही लोगों को कैंसर से बचाव, लक्षण व उपचार की जानकारी दी। सीएमएचओ डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि एनसीडी कार्यक्रम के तहत जिले में लोगों को कैंसर संबंधी स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है, लेकिन निदेशालय स्तर से जयपुर के कैंसर विशेषज्ञों की टीम भी शिविर का आयोजन कर स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है, ताकि आमजन लाभान्वित हो। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक महरिया ने बताया कि मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग वैन का 28 नवम्बर को सीएचसी खाट्वास्थानजी, 29 को सीएचसी पलसान तथा 30 नवम्बर को सीएचसी खण्डेला में शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने शिविरों में कॉमन कैंसर, स्नाइक्रल, ब्रस्ट, ओरल व फेफड़ों के कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। संभावित कैंसर रोगियों को एस्पएमएस अस्पताल जयपुर में आगे की जांच व उपचार के लिए रेफर किया जाएगा।

शिविर में 116 यूनिट रक्त एकत्रित

पाटन (निर्स)। निकटवर्ती ग्राम पंचायत डाबला में स्थित सेठ नाथाराम अग्रवाल महामना गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल में टानिया चौधरी पुत्री अजीत चौधरी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर टानिया ह्यूमन हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 116 यूनिट का संग्रहण किया गया। अजीत चौधरी डाबला ने जानकारी देते हुए बताया कि एस्पएमएस अस्पताल जयपुर से आई हुई टीम ने 48 यूनिट एवं जनिहत ब्लड सेंटर अमरेश रोड जयपुर ने 68 यूनिट ब्लड का संग्रहण किया। रक्तदान शिविर प्रार्थना 9 बजे से 3 बजे तक आयोजित रहा, जिसमें आसपास के लोगों ने बढ-चढ कर ब्लड डोनेट किया। इस दौरान नीमकाथना विधायक सुरेश मोदी, सीबीआई पुलिस अधीक्षक रामचतार यादव, पूर्व प्रधान कांता प्रसाद मंगर, भाजपा नेता करण सिंह तंवर, पूर्व प्रिंसिपल शारव मूल यादव, जिला परिषद सदस्य राजपाल डोई, प्रवीण जाखड़, डाबला स्कूल के प्रिंसिपल, पंचायत समिति प्रधान सुवालाल सैनी, मनोज बंसिया, डॉक्टर रणजीत मरारानिया, महेश गिराटी, हवा सिंह यादव, कृष्ण खटाना भी ग्रुप नीमकाथना सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

क्षमता संवर्धन कार्यशाला का शुभारंभ

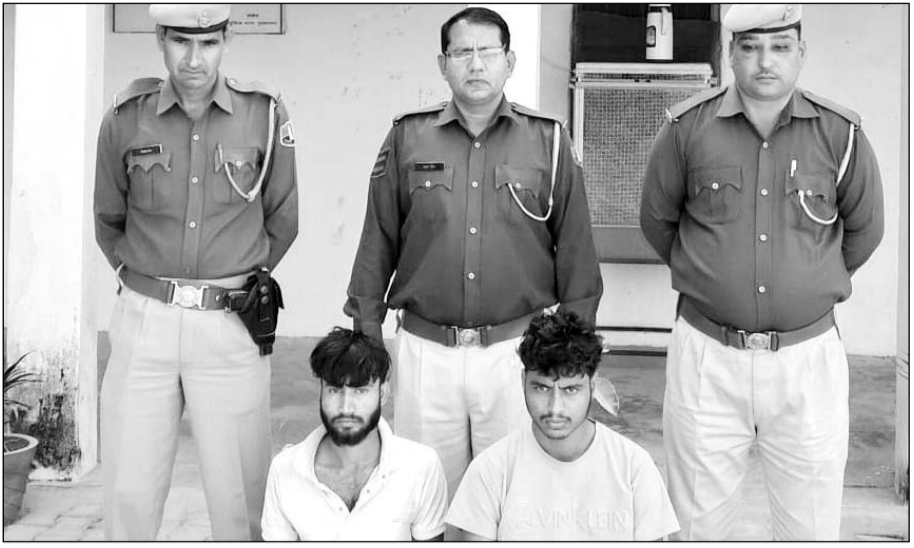
चूरू, (कासं.)। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उच्चयुक्त के तत्वावधान में जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान की ओर से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में डाइट झुंझून, सीकर, राजसमंद व चूरू के शैक्षणिक स्टफ संभागी के रूप में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद सिंह राठौड़ ने कहा कि डाइट स्टफ की जिम्मेदारी है कि वह अपने जिले के विद्यालयों में नवाचार एवं गतिविधि आधारित शिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करे। ताकि विद्यार्थियों को सीखने की उत्सुकता बढ़े। इस अवसर पर शिविर प्रभारी भीम प्रकाश सारण, उपाचार्य नरेंद्र उपाध्याय, एसआरजी मामराज ढाका व ओमप्रकाश बारुपाल आदि ने विचार व्यक्त किया। संचालन देवेन्द्र यादव ने किया।

दुकान में आग लगाकर दुकानदार की हत्या के प्रयास के दो आरोपी गिरफ्तार

खेतड़ी, (निर्स) मेहाडा पुलिस ने बुधवार को थाना क्षेत्र के मोडी गांव में दुकान में आग लगाने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों ने दुकानदार की हत्या के प्रयास में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।

थानाधिकारी सरदारमल चौधरी ने बताया कि दो दिन पहले रणवीर सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसकी गांव में किराणा की दुकान है। जिस पर कृष्ण नाई और मनोज माली आए और अवैध रूप से सामान देकर मंथली देने की धमकी दी। जब उसने सामान देने व मंथली देने से मना किया तो दोनों ने पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगा दी।

इस दौरान आरोपियों ने दुकानदार रणवीर को भी जलाने का प्रयास किया, जिससे वह झुलस गया। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलाकर राख हो गया। घटना का दौरान शोर शराबा होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। थाने में मामला दर्ज होने के बाद सीकर एसीपी भूवन भूषण यादव ने एक विशेष टीम का गठन कर आग लगाने के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।



मेहाडा पुलिस ने दुकान में आग लगाने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्त में लिया।

पुलिस आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी कि पुलिस को सूचना मिली कि दुकान में आग लगाने के आरोपी मेहाडा में छुपे हुए हैं। जिस पर पुलिस ने दबिश देकर मोडी

निवासी मनोज पुत्र फूलचंद, कृष्ण पुत्र धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा वारदात में शामिल अन्य

आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस दौरान पुलिस टीम में थानाधिकारी सरदारमल चौधरी, एचसी हरिराम, कांस्टेबल मयंक सांगवान आदि शामिल थे।

अर्द्धनग्न होकर आमरण अनशन शुरू किया

चूरू, (कासं.)। चूरू नगरपरिषद प्रशासन की हठधर्मिता की वजह से निवर्तमान पार्षद अशोक पंवार तथा प्रीत चांवरिया अर्धनग्न होकर आमरण अनशन शुरू किया है। यहां मेहतर समाज एकता मंच के संयोजक राकेश पंवार ने बताया कि राजस्थान सरकार सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में सफाई अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के संबंध में चूरू नगर परिषद आयुक्त के द्वारा पीएफ तथा अन्य वेध दस्तावेज उपलब्ध करवाने के बावजूद भी वाल्मीकि समाज के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं जारी कर रहे हैं।

आज उसी के विरोध स्वरूप वर्तमान मनोनीत पार्षद अशोक पंवार तथा प्रीत चांवरिया के द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया है जो तब तक जारी रहेगा जब तक वाजिब मांगों पूरी नहीं की जायेगी। आज सफाई कर्मचारी भर्ती की अंतिम दिनांक होने के बावजूद भी सैकड़ों लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं। आयुक्त के द्वारा

आबकारी, यातायात, खनिज, पंजीयन एवं मुद्रांक, वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की बैठक ली

सीकर (निर्स)। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बुधवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने आबकारी, यातायात, खनिज, पंजीयन एवं मुद्रांक, वाणिज्य कर विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्यों में शर्त-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

बैठक में जिला कलेक्टर शर्मा ने कहा कि आबकारी विभाग ने 525.48 लक्ष्यों के विरुद्ध 241.92, यातायात 251.64 के विरुद्ध 136.93, खनिज 59.57 के विरुद्ध 25.01, पंजीयन एवं मुद्रांक 218.37 के विरुद्ध 106.25, वाणिज्य कर 180.21 के विरुद्ध 80.46 ही राजस्व लक्ष्य अर्जित किए हैं जो काफी कम है। उन्होंने पंजीयन एवं मुद्रांक तथा यातायात विभाग को निर्देश दिए कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्तिियों के लिए विशेष प्रयास करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने आबकारी विभाग को बंदोबस्त से शेष रही दुकानों का बंदोबस्त करने, जब्त वाहनों की निलामी के संबंध में प्रभावी कार्यवाही किए जाने, जिले में हरियाणा से आने वाली अवैध शराब पर अंकुश के लिए सघन जांच अभियान चलाये जाने तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को एक वारियर कर के रूप में 160 करोड़ रूपये की वसूली जिसका पंजीयन डीलर द्वारा किया जाता है जमा होगा।

वहां के डीलरों को नियमानुसार कर वसूली के लिए पाबंद करना सुनिश्चित करें और अवैध लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बकाया कर वसूली की कार्य योजना बनाई जाए।

उन्होंने कहा कि पवर्तन कार्यवाही के द्वारा बकाया कर राजस्व प्राप्ति, लाईसेंस फीस एवं अन्य फीस के रूप में राशि प्राप्ति के विशेष प्रयास किए जाए।

जिला कलेक्टर शर्मा ने खनिज विभाग को शेष खनन पट्टों को निलामी

दो खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ



अभय कसागा

मासूम कुमारी

चूरू, (कासं)। बास ढाकान के शास्त्री पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के दो कुश्ती खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। संस्था के संचालक सेवानिवृत्त इस्पेक्टर देवेन्द्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 110 किलो के छात्र अभय कसागा और 40 किलो की छात्रा मासूम कुमारी का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। संस्था के प्रधानाचार्य सुप्रवीरलाल शर्मा ने बताया कि कुश्ती की राष्ट्रीय प्रतियोगिता दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आगामी 17 दिसंबर से होगी। निदेशक मुख्याचार चौधरी ने बताया

कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय परिसर में ही खेल अकादमी शुरू की गई है। सतयुर खेल प्रशिक्षण संस्थान के कोच शेर सिंह ने बताया कि यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इस दौरान हरलाल बुरडक, सतवीर ढाका, जयप्रकाश गढ़वाल लोहसना छोटा, जोगेंद्र सिंह महालाणा, मांगीलाल गुर्जर, संदीप कुमार, दिलीप कुमार, श्रीमती सुमन देवी, विद्या देवी, संजुलता देवी, ललिता कुमारी, सोनू कुमार, लीलाधर ढाका आदि मौजूद थे।

स्काउट गाइड मिनी जंबूरी का आयोजन आज से

झुंझुनू, (निर्स)। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय झुंझुनू के तत्वावधान में जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता रैली (मिनी जंबूरी) का आयोजन 28 नवंबर से दो दिसंबर तक स्काउट व जेपी जानू स्कूल खेल मैदान में किया जा रहा है।

सीओ स्काउट महेश कलावत ने बताया कि मिनी जंबूरी की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एडीएम डॉ. अजय कुमार आर्य ने जंबूरी स्थल का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मिनी जंबूरी में झुंझून जिले के 140 स्कूलों के 1500 से अधिक स्काउट गाइड स्काउट गाइड सहभागिता करेंगे तथा स्काउट गाइड के विभिन्न कौशल विधाओं, प्रदर्शनी, मार्च पास्ट, ड्रिल, लोक कला, लोक नृत्य, विचारित्र वेशभूषा, साहसिक प्रदर्शन, नगर प्रश्मण, बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ रैली सहित विभिन्न विधाओं का जीवंत प्रदर्शन करेंगे।

रैली के दौरान स्काउट्स गाइड्स को देश के लिए सुयोग्य नागरिक बनने की

पुरुष नसबंदी पखवाड़ा-2024 के तहत आज से

सीकर (निर्स)। चिकित्सा विभाग की परिवार कल्याण सेवाओं में प्राप्ति तथा उच्च प्रजनन दर को 2.0 प्राप्त करने के बाद अभी भी महिलाएं परिवार नियोजन की जिम्मेदारी प्रमुखता से उठाती है। परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी को बढ़ावा देने और नसबंदी के तरीकों जैसे पुरुष नसबंदी व कण्डोम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग की ओर से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि पखवाड़े के तहत स्वस्थ मां, स्वस्थ बच्चा, जब पति का हो परिवार नियोजन में योगदान अच्छा स्लोगन पर आधारित गतिविधियों का जा रही है।

उन्होंने बताया कि 28 नवम्बर से चार दिवसीय तक पखवाड़े का द्वितीय चरण को सेवा वितरण सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों, आशा सहयोगिनीयों, आंगनावाडी कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में योग्य दम्पतियों से संपर्क कर उनको कर उनको पुरुष नसबंदी कराने के लिए

‘परिवार नियोजन में बढ़ेगी पुरुषों की भागीदारी’

प्रेरित किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ हर्षल चौधरी ने बताया कि पखवाड़े के तहत चिकित्सा संस्थानों पर पुरुष लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण नसबंदी सेवाएं प्रदान के साथ जनसंख्या स्थिरीकरण में पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। पखवाड़े के तहत 21 से 27 नवम्बर तक मोबिलाइजेशन सप्ताह मनाया गया।

मोबिलाइजेशन सप्ताह में स्वास्थ्य कर्मियों, आशा सहयोगिनीयों, आंगनावाडी कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में योग्य दम्पतियों से संपर्क कर उनको पुरुषों की परिवार नियोजन में

सहभागिता, परिवार नियोजन के उपलब्ध साधनों की जानकारी, सीमित परिवार के लाभ, विवाह की सही आयु (लड़के को 21 वर्ष एवं लड़की को 18 वर्ष), विवाह के बाद कम से कम दो वर्ष बाद पहला बच्चा, पहले और दूसरे बच्चे में कम से कम तीन साल का अंतर रखने, प्रसवोत्तर परिवार कल्याण सेवाओं की उपलब्धता, गर्भवती पश्चात परिवार सेवाओं की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि गुरुवार 28 नवम्बर से चार दिसम्बर तक पखवाड़े के द्वितीय चरण को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए जिले के दो दिसम्बर को एचडीएच फतेहपुर, तीन दिसम्बर को सीएचसी रिंगस, चार दिसम्बर को जिला अस्पताल लक्ष्मणगढ़ एवं सीकर स्थी खण्डेला में स्वास्थ्य कर्मियों, आशा सहयोगिनीयों, आंगनावाडी कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में योग्य दम्पतियों से संपर्क कर उनको पुरुषों की परिवार नियोजन में

विद्यार्थियों को टाई बेल्ट वितरित

सादुलपुर, (निर्स)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हांसियावास में सीनियर टीचर राजकण्ठ की प्रेरणा से दिगारला निवासी कृष्ण कुमार अग्रवाल ने सभी विद्यार्थियों को टाई बेल्ट प्रदान किया। इसके अलावा उन्होंने अपार आईडी बनने के बाद सभी विद्यार्थियों को परिचय पत्र उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा है।

बुधवार दोपहर दो बजे समीर पुनिया ने प्रेस वक्त्रिपति में बताया कि कृष्ण कुमार अग्रवाल ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए और विद्यार्थियों के प्रति स्नेह दिखाते हुए अपनी खुशी से यह सहयोग प्रदान किया है। तथा कहा कि कृष्ण कुमार अग्रवाल खुद ग्रामीण अंचल से हैं और वर्तमान में दिल्ली में अपना निजी कारोबार है। इस अवसर पर संस्था प्रधान अनिल कुमार ने उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मनीता कुमारी, अशोक चौधरी, विनोद शर्मा, हरपाल सहरावत, ओम सहारण एवं वरिष्ठ सहायक मंदीप सहारा ने भी कृष्ण कुमार अग्रवाल का आभार जताया और विद्यालय में सहभागिता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर अध्यापिका सुमन, नरेंद्रकुमार, शाहिद खान व राहुल आदि भी मौजूद रहे।

नौ माह से लम्बित बेरोजगारी भत्ते के 1.2.53 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए जाने की मांग

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को पत्र लिखा

फिल्म निर्माता बोले कि कला एवं संस्कृति मंत्री रहे डॉ. बीडी कल्ला की ओर से आज तक राजस्थानी सिनेमा हेतु एक शब्द भी नहीं बोला है

एकशन लिया जाता है। हालांकि कई बेरोजगारों को उम्मीद नहीं है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की ओर से राजेन्द्र राठौड़ के पुत्र पर कोई ध्यान दिया जावेगा। एक परेशान बेरोजगार ने राजेन्द्र राठौड़ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पण सुणती कौनी लगी। दूसरी ओर कला एवं संस्कृति विभाग भी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के पास है। दुर्भाग्य की बात है कि कला

एवं संस्कृति मंत्री के रूप में दिया कुमारी ने आज तक राजस्थानी सिनेमा हेतु एक शब्द भी नहीं बोला है। राजस्थानी कला एवं सिनेमा का विकास करना तो बहुत दूर की बात है। इस संबंध में फिल्म निर्माताओं का कहना है कि दिया कुमारी ने तो राजस्थानी सिनेमा को हाशिए से बाहर धकेलने वाले कांग्रेस सरकार में कला एवं संस्कृति मंत्री रहे डॉ. बीडी कल्ला को भी भला कहलवा दिया है। कल्ला अपने किए का फल प्राप्त कर चुके हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा वंचित रखी गई राजस्थानी फिल्मों को समय रहते अनुदान राशि जारी नहीं की तो कल्ला की तरह ही दिया कुमारी को भी फल प्राप्त होगा। यह वंचित रहे फिल्म निर्माताओं की आत्मा से निकली हुई आवाज है, जो पार जाएगा।

बेरोजगार युवा हों, वंचित फिल्म निर्माता हों या अन्य योजना में पात्र होते हुए भी लाभ नहीं मिलने वाले लोग हों, आखिर सरकार इनकी ओर ध्यान क्यों दे रही है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भावनाओं के साथ सरासर अन्याय नहीं है तो और क्या है।

विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करने की समीक्षा की

चूरू, (कासं)। विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करने की समीक्षा बैठक का आयोजन पंचायत समिति सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद सिंह राठौड़ ने बैठक में उपस्थित चूरू ब्लॉक के सभी निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान एवं यू डाइस प्रभारियों को 30 नवंबर तक सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करने के निर्देश दिए। समग्र शिक्षा चूरू के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक संतोष महर्षि ने अपार आईडी के महत्व को बताते हुए कहा कि सभी राजकीय व निजी विद्यालयों के संपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि को एक साथ रखने के उद्देश्य से वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के मद्देनजर अपार का कार्य प्रारंभ किया गया, इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी की 12 अंकों की एक यूनिट का माध्यम से जनरेट किया जाना है जो कि विद्यार्थी के जीवनपर्यंत यूनिट शैक्षणिक पहचान के रूप में उपयोग में ली जाएगी।

विद्यार्थकों के स्थिरकर के लिए समन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5) न्यायालय SDO साहाय्यक नैनाका बाग अंचल एच। वाड बाबत दावा। वाद संख्या 178/2024 सन। वनम मुनेश पत्नी सुरेश कुमार जाति डाटा निवासी बास किराताना तहसील राजगढ़ जिला चूरू ने आपके विरुद्ध नकल सलाना में के लिए वाद पंजियन किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 06 मार्च 12 सन 2024 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपस्थित (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे वकील द्वारा उपस्थित हो सकते हैं। जिसे सत्यता सभी साक्षरान प्रमाणों का उत्तर दे सके या जिसेकें कया देना कोई कठिनाई हो उसे सब प्रमाणों का उत्तर दे सके। आपके यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन प्रतिकक्षा का शिक्का साक्षर अधिकार करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कले में या शक्ति में हैं तथा उन्हें दिन पर आपकी प्रतिकक्षा या दायित्व / मुद्राई का दावा / प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर दावे चाहें आपके कले में या शक्ति में हो अपनी प्रतिकक्षा या सुनवाई के दावे या प्रतिदावे के सम्बन्ध में साक्षर क रूप में निर्भर कर रहे हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उत्प्रेक्षित करके वे वाद उपलब्ध की जाने वाली सुधि में प्रेषित करें। आपके सुचित किया जाता है यदि आप उत्तर बताई गई तारीख को वाद न्यायालय में उपस्थित नहीं होगें तो इस की सुनवाई में अन्वेषण निवारण का अधिकार अनुपस्थिति में किया जाएगा। यह वाद ता. 27 मार्च 11 सन 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। आशा के-उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

जवाई बांध के पानी पर जालोर का हक तय करने को लेकर किसानों ने रास्ते जाम किए

विधायक के घर का रास्ता बंद कर विरोध प्रदर्शन किया

जालोर, (कांस)। जालोर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले कलकट्टे के समक्ष जारी महापड़ाव के दसवें दिन बुधवार को किसानों ने विभिन्न संगठनों के सहयोग से चक्का जाम आंदोलन शुरू किया। किसानों ने जालोर में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों में ट्रैक्टर खड़े कर मार्ग अवरुद्ध कर जाम लगा दिया। व्यापारियों ने भी किसानों का समर्थन देते हुए बुधवार को पूरे दिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इससे बाजारों में सन्नाटा पसर रहा।

सड़कों पर टायर आदि जलकर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं जालोर विधायक व मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के घर का रास्ता बंद कर उनके घर के समक्ष भी किसानों ने अपना रोष प्रकट किया। दिनभर किसान नेताओं ने महापड़ाव स्थल पर सम्बोधित करते हुए जवाई बांध के पानी पर जालोर का हक तय करने को लेकर पूरजाम मांग उठाई।

जालोर में जवाई बांध के पानी पर जालोर के लिए एक तिहाई हक तय



जवाई बांध के पानी पर जालोर के हक को लेकर चल रहा आंदोलन दसवें दिन भी जारी रहा।

करने की मांग को लेकर किसानों के महापड़ाव ने दसवें दिन बुधवार को उग्र रूप ले लिया। सरकार द्वारा किसानों के महापड़ाव के बाद भी सकारात्मक

हल नहीं निकालने से किसानों के सन्न का बांध बुधवार को टूटा और जालोर के करीब तीन सौ गांवों के हजारों की संख्या में किसान अपने अपने ट्रैक्टर

लेकर जिला मुख्यालय पहुंच गये। किसानों ने सड़कों पर उतर जालोर शहर में प्रवेश करने वाले समस्त मार्ग पर ट्रैक्टर खड़े कर मार्ग को बंद कर

दिया। जिसके चलते जालोर में आवागमन पूर्णतः बंद हो गया तथा किसानों ने हरिदेव जोशी सर्किल, हाँप्पीटल चौराहा, कलकट्टे के समक्ष

■ किसानों ने जालोर में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों में ट्रैक्टर खड़े कर मार्ग अवरुद्ध कर दिया

टायर व लड़कियां जलाकर मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने जालोर से निकलने वाले जोधपुर बाइपैस नेशनल हाईवे 325 का रास्ता बंद कर दिया तथा रोडवेज बसों को भी रोक दिया।

भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष रतनसिंह ने महापड़ाव स्थल पर सम्बोधित करते हुए कहा कि जवाई बांध के पानी पर जालोर के लिए हक तय करने को लेकर मांग लम्बे समय तक चल रही है। हमारे स्थानीय नेताओं की कमजोर पैरवी के चलते जालोर के लिए जवाई बांध के पानी का हक तय अभी तक नहीं हुआ। जिसके चलते हमेशा किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा।

बसपा नेता न्यांगली को गोली मारने का फरार आरोपी गिरफ्तार

सादलपुर, (निर्स)। बसपा नेता वीरेंद्र सिंह पर फायरिंग करने के मामले में साधु बनकर अलग-अलग ठिकाने बदल कर पुलिस से छुपता हुआ 10 सालों से फरार स्याही वारंटी को राजगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। बुधवार शाम तीन बजे दी जानकारी में थाना अधिकारी पुष्पेंद्र झाड़िया ने बताया कि महा निरीक्षक पुलिस सीकर रेंज की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व अवैध आगेंवास्तों के विरुद्ध कार्रवाई के चरिते स्थानीय पुलिस अधिकारियों के सुपरविजन में गठित टीम ने दस साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि पुलिस लगातार साक्ष्य इकट्ठा कर 10 सालों से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही थी।

उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी जोधपुर क्षेत्र में साधु बनकर घूम रहा है, जिस पर टीम जोधपुर पहुंची एवं आसपास क्षेत्र में आम सूचना संकलन करते हुए थाना क्षेत्र के सरदारपुरा में पहुंची। जहां वांछित आरोपी रमेश पुत्र धर्मातर जाट

■ साधु बनकर ठिकाने बदलकर आरोपी रहा था जोधपुर

■ राजगढ़ थाना पुलिस ने न्यायालय में पेश कर आरोपी को भेजा जेल में

निवासी गावड पुलिस थाना सदर हिसार जिला हिसार हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां न्यायाधीश ने आरोपी को जेल भिजवा दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी बड़ा शातिर है, जो दस साल से साधु करते हुए इस क्षेत्र में अलग-अलग ठिकाने पर रहते हुए फरार चल रहा था। आरोपी को गिरफ्तार करने में कांस्टेबल महेंद्र कुमार व अजय कुमार कास्टेबल की विशेष भूमिका रही। उन्होंने बताया कि बसपा नेता वीरेंद्र न्यांगली निवासी न्यांगली पीएस राजगढ़ की हत्या करने के इरादे से गोली मार दी थी। तथा मौके से आरोपी फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि अभियान जारी रहेगा।

11 युवकों को किया गिरफ्तार

सादलपुर, (निर्स)। राजगढ़ थाना पुलिस ने गैंगस्टर को फॉलो करने वाले तथा आतंजन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के चलते 11 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की है। बुधवार शाम तीन बजे दी जानकारी में थाना अधिकारी पुष्पेंद्र झाड़िया ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान गैंगस्टरों को फॉलो करने वाले आतंजन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान स्थानीय अधिकारियों के सुपरविजन में

चार अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा पुलिस टीमों ने थाना क्षेत्र में अपराधियों के घर व संभावित ठिकानों पर दबिश देकर बुधवार को 11 युवकों को गिरफ्तार करके उन्हें थाना पुलिस कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई के अंतर्गत राहुल, तोफीक पटान, समीर, जहीर खान, मोहम्मद सफीक, दीपेंद्र, अल्लाफ, कैलाश, रस्तम और रहमान को हिरासत में लिया गया है। इनके खिलाफ 107 बीएसएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

अजमेर दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा कोर्ट ने किया मंजूर

20 दिसंबर को होगी मामले की सुनवाई

अजमेर, (कांस)। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से 23 सितम्बर 2024 को अजमेर के सिविल न्यायालय में किए गए दायर वाद पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले को सुनने योग्य मानते हुए अल्प संख्यक मंत्रालय, ए एस आइ व दरगाह कमेटी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश जारी करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसम्बर 2024 तय की है।

याचिकाकर्ता हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि 23 सितंबर को अजमेर कोर्ट में वाद दायर किया था। याचिका में दरगाह कमेटी व अल्पसंख्यक मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पार्टी बनाया गया है। विश्वविख्यात ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर बताने का दावा न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र व) अजमेर नगर पश्चिम की अदालत में पेश किया गया है। दिल्ली निवासी हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता ईश्वर सिंह और योगेश सुरोलिया ने दरगाह कमेटी के कथित अनधिकृत कब्जा हटाने संबंधी वाद दो महीने पहले दायर किया था। इस दावे को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई।

वादी ने अपने तर्कों के आधार पर बताया कि इतिहासविद हरबिलास शास्त्री की पुस्तक में दरगाह में मंदिर होने का खुलासा किया गया था। उन्होंने कहा कि जहां भगवान शिव का मंदिर



कोर्ट परिसर में मौजूद हिंदू पक्षकार विष्णु गुप्ता।

होता है, वहां पर झरना एवं कुआं होता है। दरगाह में भी झालारा और कुआं है, जिससे उनका दावा और मजबूत हो जाता है। अधिवक्ताओं ने बताया कि भगवान महादेव प्रथम पक्षकार हैं और द्वितीय पक्षकार विष्णु गुप्ता हैं। अयोध्या विवाद में भी इसी तरह का दावा प्रस्तुत किया गया था और भगवान को नाबालिग मानते हुए उनके भक्त को द्वितीय पक्षकार बनाया गया था। इसी आधार पर विष्णु गुप्ता इस मामले में द्वितीय पक्षकार हैं। कोर्ट ने विष्णु गुप्ता को कोर्ट में पेश कर लिया। दिल्ली से आए एडवोकेट रामस्वरूप बिश्नोई ने बताया कि 38 पेज का वाद पेश किया गया। इसमें कहा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर है। दरगाह की बनावट और शिव मंदिर के प्रमाण के संबंध में भी

सबूत पेश किए गए हैं। यह है मामला :- वादी विष्णु गुप्ता द्वारा सितंबर माह में एसीजेएम कोर्ट में अजमेर की दरगाह में मंदिर होने का दावा पेश किया था, लेकिन क्षेत्राधिकार के मामले में न्यायाधीश ने संबंधित कोर्ट में वाद दायर करने के आदेश दिए थे। वादी द्वारा अंग्रेजी में दावा पेश करने के मामले में हिंदी में दावा पेश करने के लिए कहा गया था। गुप्ता ने 4 अक्टूबर को अजमेर की जिला एवं सत्र न्यायालय में वाद ट्रांसफर के लिए अर्जी पेश की थी। 5 नवंबर को गुप्ता को वाद वापस लेने के लिए धमकी मिली, इसके बाद उन्होंने अजमेर के किसानगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जिसकी जांच लंबित है। 25 नवंबर को गुप्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र व) अजमेर नगर पश्चिम की अदालत में वाद पेश किया

जहां तीन दिन लगातार सुनवाई हुई और बुधवार को कोर्ट ने दावा मंजूर कर लिया। अदालत में दिए तर्कों: वादी के अधिवक्ता ने बताया कि 38 पेज के दायर वाद में 38 बिंदुओं में तर्क दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से सर्वे किया जा सकता है। ज्ञानवापी की तरह 1991 पूजा स्थल अधिनियम कानून यहां लागू नहीं होगा। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्यवाही: अदालत में दावा मंजूर होने के बाद अजमेर का खुफिया विभाग सक्रिय हो गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्तचर विभाग दरगाह सहित परिधि क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए है। जिला पुलिस की साइबर सेल सोशल साइट्स पर विशेष नजर रखे हुए हैं, अफवाह फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

सिटी पैलेस में धूपी दर्शन के बाद पूर्व राजपरिवार में छिड़ा विवाद खत्म

विश्वराज सिंह ने सुबह किये एकलिंगजी के दर्शन, शाम को पहुंचे धूपी दर्शन

उदयपुर, (कांस)। मेवाड़ राजघराने की परंपराओं और आस्थाओं के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रहा विवाद बुधवार को समाप्त हो गया। उदयपुर के पूर्व राजघराने के बतौर मुखिया विश्वराज सिंह ने बुधवार को एकलिंगजी भगवान के दर्शन करके आस्था और परंपरा की एक और कड़ी जोड़ी, और शाम को सिटी पैलेस में धूपी के दर्शन कर परंपरा को पूरा किया। परंपरा अनुसार राजतिलक की रस्म के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ शाम करीब 6.15 बजे सिटी पैलेस में धूपी दर्शन के लिए पहुंचे। इस घटनाक्रम को लेकर राजघराने के समर्थकों ने खुशी का इजहार किया और क्षेत्रीय उत्साह के साथ आतिशबाजी की।



विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कैलाश पुरी में किए एकलिंगजी के दर्शन।

मेवाड़ को धूपी के दर्शन कराए जाने पर सहमति बनी। इसके बाद दूधतलाई स्थित प्रवेश द्वार से विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों ने सिटी पैलेस में प्रवेश किया। जहां आस्था और परंपरा की मिसाल पेश की गई। यह घटना ने केवल मेवाड़ राजघराने के आस्था और परंपरा को एक बार फिर स्थापित करती है बल्कि यह भी साबित करती है कि

जब धार्मिक आस्थाएं और परिवार की परंपराएं एक साथ खड़ी होती हैं तो विवादों के बावजूद समाधान का रास्ता निकल ही आता है। इससे पहले विश्वराज सिंह ने राजतिलक की रस्म के 48 वें बाद बुधवार सुबह दर्शन के लिए सिटी पैलेस में प्रवेश किया। इसके बाद हुई शोक भंग की रस्म में उन्हें रंगीन पगड़ी पहनाई गई।

विश्वराज सिंह के निवास पर परिवार के शोक भंग की रस्म को निभाई गई। इससे पहले बुधवार सुबह भी सिटी पैलेस के गेट बंद रहे। किसी भी विवाद से निपटने के लिए सिटी पैलेस के बाहर, समोर बाग के बाहर पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। सिटी पैलेस के आसपास तो घारा 163 (पहले 144) लागू है। वहीं, मंगलवार को इस पूरे विवाद पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। विश्वराज सिंह मेवाड़ और लक्ष्यराज सिंह ने एक-दूसरे को सोमवार को हुई हिंसक झड़प के जिम्मेदार बताया। दोनों ने ही सरकार और जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाए। विश्वराज ने कहा, सरकार मां बैठे एक व्यक्ति के इशारे पर पूरा विवाद हो रहा है। इधर मेवाड़ राजपरिवार के वंशजों स्वर्गीय महाराणा महेन्द्र सिंह मेवाड़ के पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह के बीच के पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बीच सिटी पैलेस में धूपी दर्शन को लेकर चल रहे विवाद पर मंगलवार रात को लक्ष्यराज सिंह

मेवाड़ पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा वे हमारे घरों में जबरन घुसने के लिए सरकार से दबाव बना रहे हैं। मैं उदयपुर में कानून ढूँढ रहा हूँ कि कहाँ है। लक्ष्यराज ने स्पष्ट किया कि किसी की कोई मांग है तो उसके लिए कानूनी रास्ता अपनाए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। गुंडगर्दी से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हालांकि लक्ष्यराज पत्रकारों के सबालों का जवाब दिए बगैर बस अपनी बात कहकर चले गए। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने शहर के सिटी पैलेस के आसपास के क्षेत्र में लोक शान्ति कायम रखने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के प्रावधानों को लागू किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के बीच धूपी दर्शन को लेकर उभरे विवाद के चलते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जगदीश चौक से 500 मीटर के परिसर में एवं रंग निवास पर्यटन पुलिस थाना तक जो कि पुलिस थाना घण्टाघर एवं पुलिस थाना सूरजपोल की सीमाओं के अन्दर आता है, उक्त सीमाओं में किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, नातक रासायनिक पदार्थ एवं आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, बंदूक, राईफल व अन्य धारादार हथियार जैसे तलवार, गंडासा, फरसा, चाकू, धारला, क्रुपाण, बर्फी, गुप्ती, कट्टा, घाटिया, आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो भूयोग न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा।

25 लाख का गबन करने वाला कर्मचारी चढ़ा पुलिस के हत्थे

अजमेर, (कांस)। पालारस्थित गोदाम में काम करने वाले एक युवक ने 25 लाख रुपए का गबन किया है। युवक दस साल से यहा पर काम कर रहा था। गोदाम मालिक ने जब स्टॉक की जांच की तो मामला उजागर हुआ। उन्होंने आदर्शनगर थाने में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसे बुधवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। थाने के हैड कांस्टेबल श्रीकिशन ने बताया कि धोला भाटा निवासी आशीष वर्मा पालार स्थित गोदाम में पिछले दस साल से काम कर रहा था। गोदाम मालिक अखिलेश जैन ने पुलिस को बताया कि आशीष दस साल से

उसके यहां पर काम कर रहा था। इस दौरान उसने धीरे-धीरे 25 लाख रुपये का गबन कर लिया। गोदाम का स्टॉक कम पाए जाने पर जांच के दौरान सामने आया कि आशीष ने बड़ी चालाकी से गोदाम वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर करके यह लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। जैसे ही आरोपी कार्यवाही की भनक लगी तो उसने काम पर आना बंद कर दिया। मामला सामने आने के बाद जैन की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गबन में आशिष के साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

हादसे में एक जने की मौत

कोटा, (निर्स)। कोटा-बारां हाईवे नॉर्दन बाईपास पर झालीपुरा के समीप एक ट्रक का टायर फटने से घायल हुये दुकानदार को उपचार के लिये एम्बीएस अस्पताल में भर्ती करवाया जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गयी। मृतक कोटा के छावनी निवासी अब्दुल रहीम (45) है। जानकारी के अनुसार अब्दुल

रहीम की झालीपुरा के पास टायर की दुकान है। बुधवार सुबह एक ट्रक दुकान से सामने आकर खड़ा हुआ और ड्राइवर स्थान ही हवा भरने लगा जिससे ज्यादा हवा भरने से टायर में अचानक घमाका हो गया। जिसकी चपेट में आने से अब्दुल रहीम घायल हो गया। जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(सब्सिडियरी ऑफ़ इंडियन स्टेट्स लिमिटेड), कोटा, राज. (पूणं वॉ टोल फ्री), अजमेर नगर से जामने, प्रस्ताव संशोधित है,
कॉन्ट्रैक्ट नं. 01/17/24/23, डीएम नं. 21/44/23, E-mail : gpa-rsrb@rajasthan.gov.in, CN : 1195111200562003936
क्रमांक - पं/नजा /RSCB/प्रस्ताव/2024-25/7086 दिनांक - 26/11/2024

ई-निविदा सूचना - 15
निगम में कार्य आधार पर कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर मध्य प्रशिक्षित कार्मिक (मशीन विद मैन) एवं मानव संसाधन (व.श्रे. कर्मचारी) उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता/कर्म/कंपनी से ऑनलाईन बिड आमंत्रित की जाती है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एवं बिड प्राप्त वेबसाइट पर
https://sppp.rajasthan.gov.in, https://excise.rajasthan.gov.in, https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक विदाता अपनी बिड दिनांक 29/11/2024 से 09/12/2024 राय 6:00 बजे तक https://eproc.rajasthan.gov.in ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। UBN No. :- BCL24255LOB0001
राज.सं.वा.व/सी/24/8348 कार्यवाही अधिकारी

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
क्रमांक - पं/नजा - 12029450 दिनांक - 26/11/2024
ई-निविदा सूचना संख्या :- जोन दक्षिण /14/2024-25
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से स्थिति कार्यों हेतु मुहूर्तवद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्त आदि का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.jodhpurjda.org, www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।
NIB Code :- JOD2425A0128,
UBN No. :- JOD2425WSOB00271
राज.सं.वा.व/सी/24/8351 अधिकांशी अधिकारी (देविम)

कार्यालय नगर पालिका अक्लेय जिला झालावाड (राज.)
क्रमांक - पं.नजा./2024/1601 दिनांक - 20/11/2024
ई-निविदा सूचना सं. 02/2024-25
इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या - न.पा.अ./2024/1588-1590 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा कुल 9 कार्य की अनुमानित लागत 187.00 लाख रु. की पंजीकृत संवेदकों से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित सम्स्त विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in and http://eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। UBN No. DLB24255LOB12050, DLB24255LOB12051, DLB24255LOB12052, DLB24255LOB12053, DLB24255LOB12054, DLB24255LOB12055, DLB24255LOB12056, DLB24255LOB12057, DLB24255LOB12058
अध्यक्ष अधिकांशी अधिकारी
नगर पालिका अक्लेय नगर पालिका अक्लेय

EXECUTIVE ENGINEER PWD DN-DAUSA
File No. 4816-25 Date 20/11/24
Notice Inviting Bid No-27/2024-25
Bids for Construction work under PWD Division Dausa of Nil No. 27 Year 2024-25 of Procurement are invited from interested bidders upto 11.00 AM (time) 05.12.2024 (date). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://www.eproc.rajasthan.gov.in>) / (<http://sppp.rajasthan.gov.in>) of the state; and (<http://www.pwd.rajasthan.gov.in>) departmental website. The approximate value of the procurement is Rs 185.95 Lacs
1. UBN No. PWD2425WSOB 10189
2. UBN No. PWD2425WSOB 10190
Executive Engineer
PWD Division-Dausa
DIPRC/11739/2024

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जालोर
क्रमांक-पीएमअ/2024/2220 दिनांक-21.11.2024

ई-निविदा सूचना
जिला चिकित्सालय जालोर के अंतर्गत संचालित एम्बीएस सेक्टर जालोर के लिए ठेकाओंकी व हिस्टोरिकली मशीन अपूर्णित के लिये राजस्थान लोक उपायन में धार्कशिता अभियान 2012 एवं नियम 2013 में विहित विधियों एवं विनियम विभाग द्वारा समय समय पर जारी प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत फर्मों से E-Proc. पोर्टल पर विज्ञापित की जाती है। निविदा की जांच के लिये जिला चिकित्सालय निम्नानुसार 25.31 लाख है, निविदा सूचना www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN No. MHS2425GLOB03976, NIB No. MHS2425A2744
प्रमुख चिकित्साधिकारी
जालोर
DIPRC/11743/2024

कार्यालय अधिकांशी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कोटा (राज.)
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, देवदाही परिसर, सचराय अवास ए-1, कोटा (राज.)
फोन-0744-2461550, E-mail: eemhkota@gmail.com, ee-mh-kota@gov.in
क्रमांक-849 निविदा सूचना संख्या- 17/2024-2025 दिनांक-21.11.2024
राजस्थान के राजस्थान मंत्रालय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य विधि चिकित्सालयों पर रु. 1000.00 लाख के 20 विभिन्न कार्य हेतु उच्छुक फर्मों में सर्वप्रथम प्रथम विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य/केन्द्र सरकार के अधिनियम 2002 के अन्तर्गत विनियम विभाग एवं दूर चलाय विभाग के इकाई में उच्छुक संवेदकों, जो राजस्थान सरकार के अर्थव्यवस्था के संवेदकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रश्न में ई-प्रोक्वेस्ट निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण DIPRC की वेबसाइट पर www.diproneonline.org पर देखा जा सकता है।
Sr.No. UBN NO. Sr.No. UBN NO. Sr.No. UBN NO.
1. NRH2425WSOB01525 8. NRH2425WSOB01532 15. NRH2425WSOB01539
2. NRH2425WSOB01528 9. NRH2425WSOB01533 16. NRH2425WSOB01540
3. NRH2425WSOB01527 10. NRH2425WSOB01534 17. NRH2425WSOB01541
4. NRH2425WSOB01528 11. NRH2425WSOB01535 18. NRH2425WSOB01542
5. NRH2425WSOB01529 12. NRH2425WSOB01536 19. NRH2425WSOB01543
6. NRH2425WSOB01530 13. NRH2425WSOB01537 20. NRH2425WSOB01544
7. NRH2425WSOB01531 14. NRH2425WSOB01538
DIPRC/11713/2024 अधिकांशी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चण्ड-कोटा

कार्यालय नगरपरिषद, जालोर (राज.)
हाँप्पीटल चौराहा, रेलवे स्टेशन रोड, जालोर - 343001
क्रमांक / न.पा.अ./मण्डल/ई-टेंडर/2024/4810 दिनांक: 21.11.2024
:: ई-निविदा सूचना संख्या 03/2024-25 ::
नगरपरिषद, जालोर द्वारा निम्नलिखित कार्य / सामग्री की आपूर्ति हेतु माल एवं सेवाओं के उपायन के लिए दर सूचित विधियों एवं 2024-25 दिनांक (31.03.2026) के लिए (रिट कांस्टेबल) हेतु राजस्थान लोक सेवा उपायन धार्कशिता नियम 2023 के अन्तर्गत विनियम फॉर्म, ठेकावदों, अधिष्ठाता डिस्तर, पंजीकृत, प्राधिकृत फॉर्म / आपूर्तिकर्ताओं / डिस्तर से निर्धारित प्रश्न में ई-टेंडर प्रक्रिया के अन्तर्गत निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा की संपूर्ण विवरण / शर्त ई-प्रोक्वेस्ट पोर्टल पर <https://eproc.rajasthan.gov.in> एवं <https://sppp.rajasthan.gov.in> पर देवी तथा डाउनलोड की जा सकती है-
01. NIB Code- DLB2425A3965 आयुक्त
राज.सं.वा.व/सी/24/8358 नगरपरिषद, जालोर

नगर विकास न्यास, पाली की ओर न्यास /प्रोजेक्ट विभाग से नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निष्ठांतरित प्रश्न में ई-प्रोक्वेस्ट प्रक्रिया से सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्मिक लगाने हेतु ऑन-लाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण <https://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है तथा न्यास कार्यालय, पाली में कार्य दिवस के दौरान देखा जा सकता है।
कार्य निविदा राशि यू.बी.एन नम्बर (sppp.rajasthan.gov.in)
सेवा प्रदाता के माध्यम से 15.00 लाख रु. ITP2425LRC00040
अधिकांशी अधिकारी, नगर विकास न्यास, पाली
राज.सं.वा.व/सी/24/8356 दिनांक - 25/11/2024

“राइजिंग राजस्थान” ग्लोबल बिज़नेस एक्सपो में मैन्चूफैक्चरिंग क्षेत्र में प्रदेश की क्षमता प्रदर्शित होगी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राजस्थान ग्लोबल बिज़नेस एक्सपो का भी आयोजन किया जाएगा और इसमें राजस्थान और देश भर से 100 से अधिक कंपनियों और व्यापारिक समूह भाग लेंगे। इस ग्लोबल एक्सपो में मैन्चूफैक्चरिंग क्षेत्र में राज्य की क्षमता प्रदर्शित की जाएगी और देश के औद्योगिक परिदृश्य में राजस्थान की अहम भूमिका को दिखाया जाएगा। इस एक्सपो में कई पैवेलियन भी लगाए जाएंगे, जिनमें प्रमुख रूप से राजस्थान का स्टेट-ऑफ-दी-आर्ट पैवेलियन और कुछ चुनिंदा देशों, स्टार्टअप और महिला उद्यमियों के लिए लगाए जाने वाले पैवेलियन होंगे।

■ **एक्सपो में राजस्थान और देश भर से 100 से अधिक कंपनियों और व्यापारिक समूह भाग लेंगे, राजस्थान, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और चुनिंदा देशों के होंगे विशेष पैवेलियन**

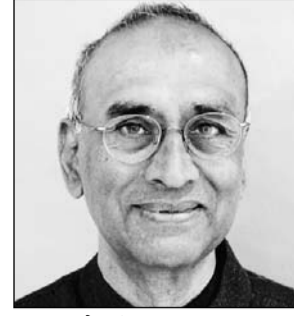
जानकारियों दी जाएंगी। इसके तहत राज्य की अर्थव्यवस्था, समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक धरोहरों, प्रमुख और नये या उभरते हुए व्यवसायिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, इसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और पहलों को भी प्रदर्शित किया जाएगा और ग्रामीण परिदृश्य को बेहतर बनाने और शहरी सुविधाओं को पुनर्जीवित करने में उनके प्रभाव के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा, इसमें उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, स्मार्ट सार्वजनिक वितरण

और विभिन्न ई-गवर्नंस पहलों को भी इंटीग्रेटेड पैनलों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा, स्टार्ट-अप पैवेलियन में राज्य में मौजूद स्टार्ट-अप को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें राज्य की प्रमुख महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप भी शामिल हैं। इसी तरह, महिला उद्यमियों के पैवेलियन में महिलाओं के नेतृत्व में सफल व्यवसायों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिन्होंने सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों और पहलों के तहत बड़ी ऊँचाइयों को हासिल किया है। इस पैवेलियन के जरिए ये

महिला उद्यमी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भाग लेने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के सामने अपने व्यवसायों की जानकारी दे सकेंगीं ताकि उनकी उद्यमशीलता देखे और सराही जाए। इसके बारे में बताते हुए राजस्थान सरकार के रीको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक इंद्रजीत सिंह ने कहा, राजस्थान ग्लोबल बिज़नेस एक्सपो उद्यमता की राजस्थानी भावना और पारंपरिक क्षमताओं के संग-संग राजस्थान को एक आधुनिक औद्योगिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर है। 10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली इस प्रदर्शनी (एक्सपो) में राजस्थान में व्यावसायिक उपस्थिति या रुचि रखने वाले कई भारतीय और विदेशी व्यापार समूह शामिल होंगे। एक्सपो में अपने पैवेलियन लगाने वाले उल्लेखनीय भारतीय व्यापार समूहों में

असाही इंडिया ग्लास, जिसने हाल ही में चित्तौड़गढ़ में एक प्रमुख प्लेट ग्लास प्लांट स्थापित किया है, जेएसडब्ल्यू एनजी, टाटा पावर, टॉरेंट ग्रुप, महिंद्रा सिटी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जेके सीमेंट, जेके टायर वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा, इस ग्लोबल बिज़नेस एक्सपो में डेनमार्क और जापान सहित कुछ चुनिंदा देश भी अपने देश के बारे में पैवेलियन लगाएंगे और आने वाले दिनों में इसमें कई और देश भी जुड़ सकते हैं। साथ ही, बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी इस एक्सपो में अपना पैवेलियन लगा रहे हैं और इनमें एचपीसीएल, गेल जैसी केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं।

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के वक्ताओं की पहली सूची की घोषणा



वेन्का रामाकृष्णन



अनुरा फेंडर



टीना ब्राऊन

जयपुर। भारत के जाने-माने फेस्टिवल क्यूरेटर एवं प्रोडक्शन हाउस टीमवर्क आर्ट्स ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बहुप्रतीक्षित 18वें एडिशन के वक्ताओं की पहली सूची जारी कर दी है। साहित्य की दुनिया के इस प्रतिष्ठित समारोह का आयोजन आगामी 30 जनवरी से 3 फरवरी के दौरान, जयपुर स्थित होटल क्लाक्स आमेर में किया जाएगा। दुनियाभर में ‘धरती पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े साहित्योत्सव’ के तौर पर प्रतिष्ठित इस फेस्टिवल के मंच पर एक बार फिर लेखकों, विचारकों और पाठकों की महफिलें जुटेंगीं जो साहित्य के हालातों और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ जुड़ाव कायम करने की इसकी अनूठी क्षमता के बारे में मिल-जुलकर विचार-मंथन करेंगीं।



जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मूल में भाषायी विविधता है, और यही वजह है कि साहित्य का यह मेला विभिन्न भाषाओं को मंच प्रदान करता है। इस साल के सत्रों में हिंदी, बांग्ला, राजस्थानी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओड़िया, संस्कृत, असमी, मलयालम, मराठी, पंजाबी और उर्दू समेत अनेक भाषाओं में कृतियों और चर्चाओं को परोसा जाएगा और इस प्रकार यह मेला समावेशिता के साथ-साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचायक होगा। 18वें एडिशन में अलग-अलग क्षेत्रों के 300 से अधिक वक्ताओं को शामिल किया गया है, जो प्रतिभागीयों को वैश्विक एवं भारतीय साहित्यिक

हस्तियों से जुड़ने का मौका देगा। वक्ताओं की पहली सूची में शामिल हैं आंद्रे एचिमान, अमिरुद्ध कनिसेट्टी, अनुरा फेंडर, अश्वनी कुमार, कावेरी माधवन, क्लाडिया डी राम, डेविड निकॉस्टी, फियोना कारावन, इरा मुखोर्ती, आइरेनोस ओकोजी, जेनी एरनबेक, जॉन वॉलेंट, कलोल भट्टाचार्जी, मैत्री विक्रमसिंघे, मनम कौल, मिरियम मार्गॉलिस, नसीम निकोलस तालेब, नाथन थ्राल, प्रयाग अकबर, प्रियंका मद्दू, स्टोफन ग्रॉनब्लाट, टीना ब्राउन, वी वी गणेशनंदन, वैकी रामाकृष्णन, और यरोस्लावा त्रोफिमोफ सरीखी साहित्यिक दुनिया की प्रतिभाएं जो उत्सव के दौरान विचारों से भरे साहित्यिक चर्चाओं का भरोसा दिलाती हैं। जानी मानी लेखक और फेस्टिवल की सह-निदेशक नमिता गोखले का कहना है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हमेशा से ही कहानियों, नए विचारों और संस्कृतियों का संगम रहा है। अब जबकि हम 18वें एडिशन की तैयारी में जुटे हैं, तो हम वास्तव में, प्रेरित करने, चुनौती देने और एकजुट करने की साहित्य की ताकत का जश्न मना रहे हैं। इस साल, हम लेखकों, कवियों और विचारकों की ऐसी अविश्वसनीय पंक्तियों का स्वागत करने जा रहे हैं जो दर्शकों के साथ कभी न भुलाए जा सकने वाले संवाद-सत्रों का नेतृत्व करेंगीं।

विनम्र रहे, निष्पक्षता से कार्य करें : देवनानी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा है कि विनम्र रहकर निष्पक्षता से कार्य करें। ईमानदारी से सोच-समझकर कर नियंत्रण लें ताकि किसी के प्रति अन्याय न हो। युवा संकल्प लेंगे तो राष्ट्र विश्व पर अविश्व पर अवश्य अग्रणी रहेगा। युवा राष्ट्र के भविष्य की आशा की किरण है। देवनानी से बुधवार को यहां राजस्थान विधान सभा में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में नव चयनित 75 प्रशिक्षु अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। देवनानी ने सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी।

■ **राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों की विधानसभाध्यक्ष से मुलाकात**

सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के.के. शर्मा, वित्तीय सलाहकार अपूर्व जोशी और उप सचिव संजीव कुमार शर्मा ने अधिकारियों को राजस्थान विधानसभा की गतिविधियों के बारे में बताया। इस मौके पर हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के डॉ. गुल फिरदौस और विनोद कुमारी भी मौजूद थीं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को विधानसभा में नई मुस्कान पोस्टर का विमोचन किया। देवनानी को डॉ. उमेश दत्त ने नई मुस्कान कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि दौसा में एक दिसम्बर को शहर के बच्चों का फ्री चैकअप किया जायेगा। देवनानी ने चिकित्सकों से कहा कि सशक्त राष्ट्र के लिए बच्चों का स्वस्थ होना आवश्यक है। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए निरन्तर कार्य करें। इस मौके पर विधान सभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के.के.शर्मा, डॉ. उमेश दत्त शर्मा, डॉ. पंकज जुत्थी और डॉ. पिप्लू त्रिवेदी मौजूद थे।

‘पशुपालकों के लिए कारगर साबित हो रही है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना’

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संसद मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशभर के पशुपालकों को आय बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना कारगर साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान पशुपालन विभाग की ओर से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 10 वर्षों में दूध उत्पादन में 63.56 प्रतिशत की बढ़ोतरी रकम की गई। वर्ष 2014-15 में जहां 146.3 मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन किया जा रहा था, वो वर्ष 2023-24 में 239.3 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया। वहीं देशभर में पशुओं की देशी नस्ल सुधार के लिए आइ.सी.एफ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 32 छहडे और बछड़ियों को जन्म दिया गया।

■ **राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के ताराकित सवाल के जवाब में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जवाब में दी जानकारी**

योजना के लक्ष्य प्राप्ति और देशभर में इस योजना से लाभान्वित किसानों को लेकर राज्यसभा में ताराकित सवाल लगाया। इसके जवाब में मन्स्युपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह जवाब दिया कि योजना से देशभर में 4 करोड़ 58 लाख 14 हजार 284 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसमें राजस्थान के 32 लाख 47 हजार 550 किसान राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित हुए। इतना ही नहीं, देशभर में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए 38 हजार से अधिक मैत्रियों को लगाया गया। इसमें राजस्थान में 771 मैत्री कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के तौर पर कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत देशी नस्लों के सुधार की दिशा में भी सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें राजस्थान की साहीवाल, थारपाकर और राठी नस्ल के पशुओं की संतति परीक्षण और नस्ल चयन कार्यक्रम शुरू किया गया। वहीं राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के दौरान पिछले तीन सालों में राजस्थान के 32.47 लाख किसान लाभान्वित हुए और 55.99 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया। इतना ही नहीं, देशभर में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए 7 नस्ल वृद्धि फार्म स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए केंद्री की ओर से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर 70 व्यक्तियों को सामुदायिक संसाधन व्यक्ति ए-हेल्प का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।

राजस्थान विधान सभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के.के.शर्मा, डॉ. उमेश दत्त शर्मा, डॉ. पंकज जुत्थी और डॉ. पिप्लू त्रिवेदी मौजूद थे।

कल्चरल डायरीज : गायन, वादन व नृत्य का साक्षी बनेगा जयपुर

■ **उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर शुरू की गई कल्चरल डायरीज के तहत दो दिवसीय सांस्कृतिक संध्या 29-30 नवम्बर को अल्बर्ट हॉल पर होगी आयोजित**

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अभिनव पहल व दिशा-निर्देशों के तहत पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई सांस्कृतिक संध्या कल्चरल डायरीज शृंखला के तहत आगामी शुक्रवार व शनिवार 29 व 30 नवम्बर को अल्बर्ट हॉल पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगीं। इन प्रस्तुतियों के दौरान जयपुरवासीयों सहित विदेशी व देशी पर्यटकों को गायन, वादन व नृत्य का शानदार संगम देखने को मिलेगा।

आकर्षण का केन्द्र रहेगा। उनके समूह का कालबेलिया नृत्य जिसमें तीन पीढ़ियों एक साथ नृत्य की प्रस्तुति देंगी। शनिवार 30 नवम्बर को जयपुर के ईंटी फोक ग्रुप युगम बैंड की प्रस्तुति के साथ लोक वाद्य यंत्र रावण हस्त्या वादन प्रस्तुत किया जाएगा। उल्लेखनीय है उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर लोक कलाकारों की मंच प्रदान करते हुए उन्हें सम्बल प्रदान करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कल्चरल डायरीज नाम से पाक्षिक सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत की गई है, इस पाक्षिक सांस्कृतिक शृंखला की पहली दो दिवसीय प्रस्तुतियां नवम्बर के दूसरे पखवाड़े में अल्बर्ट हॉल पर आयोजित हो चुकी हैं।

57 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही पांच कॉलोनियां ध्वस्त

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 तक पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा-2024 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन जयपुर शहर के 130 केन्द्रों पर होगा। छह पारियों में (प्रथम पारी प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे एवं द्वितीय पारी दोपहर 2:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक) आयोजित होने वाली परीक्षा में कुल 2 लाख 60 हजार 163 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) देवेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि परीक्षा के सुचारु एवं सफल संचालन के लिये कलक्टर के कमा नंबर 116 में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसका संचालन 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष 29 नवंबर एवं 30 नवंबर 2024 तक प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक कार्य करेगा। वहीं, 01 दिसंबर से 03 दिसंबर 2024 को प्रातः 6 बजे से परीक्षा समाप्ति उपरान्त नियंत्रण कक्ष से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण होने तक कार्य करेगा। परीक्षा के लिए कुल छह पारियों में 414 उप समन्वयक एवं 69 उडनदत्तों का तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि जयपुर स्थित परीक्षा केन्द्रों के लिए नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 0141-2206699 रहेगा।

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने करीब 57 बीघा कृषि भूमि पर काटी जा रही पांच अवैध कॉलोनिनों को ध्वस्त किया। इसके अलावा बगरू में भी आम रास्ते की 7 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया। उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्वासे ने बताया कि जैन-13 स्थित दौलतपुर रोड पर सेवामपुर डंपिंग यार्ड के पास करीब 27 बीघा निजी खातेदारी की कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी चल रही थी। कारतकारों ने कृषि भूमि को समतल करके यहां रातोंरात डामर की 7 सड़कें, बाउंड्रीवाल समेत कई निर्माण कर लिए हैं, जिन्हें बुधवार को जे.सी.बी. मशीन की मदद से ध्वस्त किया। इसी प्रकार खोरा थयामदास जाने वाले रास्ते पर स्थित ग्राम मोटू का वास में भी 6 बीघा निजी खातेदारी की कृषि भूमि पर ‘श्याम वटिका विस्तार’ के नाम से अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसी ही अवैध कॉलोनी ग्राम चौमूं में होली दरवाजे के पास 1.5

■ **जे.डी.ए. ने बगरू में 7 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया**

बीघा जमीन पर काटी गई थी। इसके अलावा बगरू में भी करीब 20 कृषि भूमि पर ‘जगन्नाथसिटी’ के नाम से चोरी छिपे कॉलोनी काटकर यहां सीमेंट ब्लॉक्स की सड़क, प्लॉट्स की बाउंड्रीवाल व अन्य निर्माण कर लिए हैं। इसके नजदीक ही 2 बीघा कृषि भूमि पर ‘जयश्री श्याम’ के नाम से कॉलोनी बसाने की तैयारी थी। कारतकारों ने कृषि भूमि का भू-रूपोत्तरण करवाये बिना और जेडीए से इजाजत लिए बगैर ही यह अवैध कॉलोनियां बसाने की कोशिश की थी। इससे राज्य सरकार और जेडीए को करोड़ों रु. के राजस्व की हानि हो रही थी। बुधवार को पांचों अवैध कॉलोनिनों पर जेडीए का बुलडोजर गराजा और सभी निर्माण ध्वस्त कर दिए गए।

मांस की पांच अवैध दुकानें सीज

जयपुर। नगर निगम हैरिटेज की पशु प्रबंधन शाखा ने मीट की अवैध दुकानों पर कार्रवाई करते हुए पांच दुकानों को सीज कर दिया। कार्रवाई के संबंध में पशु प्रबंधन शाखा उपायुक्त अनीता मिश्र ने बताया कि शाखा को लगातार बिना लाइसेंस और खुले में मांस बेचने की शिकायतें आ रही थीं। जिस पर शाखा के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मयंक लाम्बा ने रामगंज, घोड़ा निकाल रोड, हांडीपुरा, नाहरी का नाका इलाके में चल रही मीट की दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर अनियमितताएं पाई गईं। इस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 दुकानों को सीज कर दिया और करीब 250 किलो अवैध मीट को जब्त कर नष्ट करा दिया है। वहीं खुले में मांस बेचने पर पांच दुकानों से दुर्गमानी भी वसूल किया। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ मयंक लाम्बा ने बताया कि निगम आयुक्त अरुण कुमार हसीजा के निर्देश पर निगम क्षेत्र में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। शाखा रात में भी अवैध मीट बेचने और बूचडखानों पर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई में सतर्कता शाखा का भी सहयोग रहा।



नगर निगम हैरिटेज की पशु प्रबंधन शाखा ने बुधवार को परकोटा क्षेत्र में संचालित मांस की अवैध दुकानों पर कार्रवाई की।

झोटवाड़ा में खुलेंगे पांच नए आंगनबाड़ी केन्द्र

जयपुर। कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के सार्थक प्रयासों से झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। कम उम्र के बच्चों, गर्भवती-धारी महिलाओं को पोषाहार के साथ टीकाकरण व पढ़ाई की सुविधा घर के पास ही केन्द्र पर मिलेगी। ये नए आंगनबाड़ी केन्द्र इन्द्रा कॉलोनी (बिंदायक) वार्ड नं. 49, धनश्याम विहार, वार्ड नं. 51, जनकपुरी, वार्ड नं. 63, बवासियां का मोहल्ला, जोरपुरा सुंदरियावास, लोहड़ो की ढाणी, आला का वास, जोरपुरा सुंदरियावास में खुलेंगे। झोटवाड़ा की जनता ने इस सराहनीय पहल हेतु कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बच्चों को बेहतर शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र न केवल बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि महिलाओं की सशक्त बनाने और उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक होते हैं।

सिन्धु दर्शन यात्रा के लिए मिलेगी 15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के आग्रह पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सिन्धी समाज को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सिन्धी समाज की सबसे बड़ी और पवित्र मानी जाने वाली लेह-लद्दाख सिन्धु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 15 हजार रुपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सिन्धु दर्शन यात्रा में चार दिन तक लेह-लद्दाख में धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन होते हैं तथा यह यात्रा 18 जून से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होती है। सिन्धी समाज के तीर्थयात्री हर साल 23 से 26 जून तक लेह-लद्दाख में सिन्धु दर्शन यात्रा पर जाते हैं। यह यात्रा 18 जून से जम्मू एवं कश्मीर से प्रारम्भ होती है तथा 30 जून को इसका अधिकारिक समापन होता है। देवनानी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को ज्ञापन देकर आग्रह किया था कि सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी अत्यंत ही जायाओं को तरह आर्थिक सहायता दी जाए। इस पर निर्णय करते हुए राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए 15 हजार रुपए प्रति यात्री की आर्थिक सहायता की घोषणा की है।

■ **विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया था मुख्यमंत्री से आग्रह**

गौरतलब है कि वर्ष 1997 में भारत रत्न एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सिन्धु दर्शन यात्रा की शुरुआत की थी। प्रतिवर्ष यह यात्रा 23 से 26 जून तक लेह-लद्दाख में आयोजित की जाती है। इसमें बड़ी संख्या में सिंधी धर्मावलम्बी भाग लेते हैं। वेद, धनश्याम धार्मिक मान्यताओं में सिन्धु नदी का बड़ा महत्व है। लगभग सभी ग्रन्थों में सिन्धु नदी का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रगान में भी सिन्धु नदी का उल्लेख है। सिन्धी समाज में भी इष्ट देव श्री श्रुतेलाल के अवतार का जल से संबंध है। ऐसे में यह यात्रा सिन्धी धर्मावलम्बियों के लिए बड़ी पवित्र मानी जाती है। प्रतिवर्ष देश के लगभग 25 राज्यों से सिन्धी धर्मावलम्बी इस पवित्र यात्रा पर जाते हैं। यह यात्रा जम्मू एवं कश्मीर से प्रारम्भ होती है एवं लगभग 12 दिन चलती है। यात्रा में लेह-लद्दाख में विशिष्ट धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन होते हैं।

तीन पी.टी.आई. और एक व्याख्याता को एस.ओ.जी. ने गिरफ्तार किया

इन चारों आरोपियों ने डमी कैंडिडेट की मदद से परीक्षा पास की थी

जयपुर (कांस)। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को तीन पीटीआई और एक व्याख्याता को गिरफ्तार किया है। इन के खिलाफ एसओजी को हैल्पलाइन पर शिकायत मिली थी कि चारों ने डमी कैंडिडेट की मदद से परीक्षा पास की थी। इनके द्वारा पेश की गई बीपीएड की डिग्री भी फर्जी निकली। इस पर एसओजी ने तीनों के दस्तावेजों की जांच की, जांच में पुष्टि होने पर चारों को बुधवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। एस.ओ.जी. सूत्रों ने बताया कि एसओजी जयपुर के व्हाटसएप हैल्पलाइन पर शिकायत मिली थी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षक सीधी भर्ती 2022 में कुछ लोग गलत चीजों को इस्तेमाल कर परीक्षा में पास हुए और नौकरों ली। जिस पर एसओजी ने स्वरूपा राम निवासी गुडामलानी जिला बाडमेर हाल शारीरिक शिक्षक की जांच की।



उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुडा, रानीवाडा, जिला सांचोर, लादुराम निवासी दोतीवास तहसीली भीनमाल जिला जालौर हाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, वनानी भीलों की ढाणी, गुडामलानी, बाडमेर की जांच की। जांच में प्रमाणित हो गया कि इन लोगों ने अपनी जगह परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाया। तीनों आरोपियों ने उस दौरान आवेदन पत्रों में अन्य विश्वविद्यालय की बीपीएड डिग्री भर कर अन्य विश्वविद्यालय की बीपीएड डिग्री और डॉकी, भीमदत्त धारीमक विद्यालय बाडमेर, भारतम पेश कर पीटीआई की नौकरी प्राप्त की। एसओजी ने जब इन डिग्री और डमी अभ्यर्थी के पेपर में

■ **आरोपियों द्वारा पेश की गई बी.पी.एड. की डिग्री भी फर्जी निकली। एसओजी ने दस्तावेजों की जांच के बाद इन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया**

बैटने की जांच की तो यह पुष्टि हो गई। जिस पर इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी की गई। आरोपी स्वरूपा राम को जिला पुलिस अधीक्षक जालौर ज्ञानचन्द्र यादव को आरोपी लादुराम एवं भारमल को जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर नरेंद्र मीणा के निदेशन में टीम ने डिटेन कर एसओजी के सुपुर्द किया। जिस पर एसओजी ने दोनो को कोर्ट में पेश कर 7 दिन का रिमांड लिया है। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के नरिंह अस्थापक (माध्यमिक शिक्षा) द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2022 के सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा

पिकअप पलटी, 14 महिलाओं सहित 26 जने घायल

हादसे के बाद मौके पर घायलों की चीख-पुकार मच गई

भीलवाड़ा। पड़ोसी जिले शाहपुर के पारोली थाना इलाके में बुधवार सुबह टायर फटने के बाद एक पिकअप पलट गई।

हादसे में 14 महिलाओं सहित 26 लोग घायल हो गये। मौके पर घायलों की चीख-पुकार मच गई। आस-पास मौजूद लोगों व पारोली पुलिस ने घायलों को पारोली अस्पताल ले जाया गया, जहां से करीब दस घायलों को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रैफर कर दिया गया। जहां उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई।

पारोली पुलिस ने बताया कि माली समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी। बुधवार सुबह अंतिम संस्कार होने से मृतक के रिश्तेदार रण गांव से पिकअप में सवार होकर पारोली के लिए खाना हुए। यह पिकअप पारोली क्षेत्र में भूणाजी का झोंपड़ा चौराहे के पास पहुंची थी कि अचानक चलती पिकअप का पिछला टायर फट गया, जिससे यह पिकअप सड़क पर पलट आई और 20 से 25 फीट तक सड़क पर घसीटी गई। इसके चलते पिकअप में सवार लोग सड़क पर गिरने के बाद पिकअप से



पिकअप पलटने से घायल लोगों का अस्पताल में उपचार किया गया।

टकराकर घायल हो गये। करीब 26 लोग चोटिल हो गये। इनमें 14 महिलायें शामिल हैं। आस-पास मौजूद लोगों के साथ ही सूचना पर पहुंची पारोली पुलिस ने घायलों को पारोली अस्पताल पहुंचाया, जहां 10 घायलों को गंभीर चोट लगने से उन्हें

भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रैफर कर दिया, जबकि शेष का वहीं उपचार किया जा रहा है। एमजी अस्पताल में एक बुजुर्ग भुवना (60) पुत्र देवीलाल माली की मौत हो गई। हादसे में घायल मोहन (60) पुत्र मांगू माली, लादू

(30) पुत्र भुवना माली, लादू (68) पुत्र पेमा माली, किशन (14) पुत्र भंवर माली, गोपाल (40) पुत्र चुना माली, मांगू (45) पुत्र छीर माली, कमली (55) पत्नी बद्रीलाल माली, कोयली (45) पत्नी हीरा माली, मानी (11) पुत्री भैरू माली,

- पारोली पुलिस ने बताया कि माली समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई
- पिकअप का पिछला टायर फटने से पिकअप सड़क पर पलट गई

कमली (40) पत्नी शंकर माली, छोदू (25) पुत्र चूना माली, उदी (45) पत्नी भैरू माली, कांता पत्नी कालू माली, आशा (25) पत्नी लाला माली, महेंद्र (28) पुत्र रामेश्वर माली, काली माली (40), कैलाश (30) पुत्र डूंगर माली, फौरी (25) पत्नी छोदू माली, गुलाबी (40) पत्नी उदालाल माली, गोपाली (30) पत्नी राजू माली, रामकन्या (50) पत्नी भैरू माली, उदय लाल (55) पुत्र गुलाब माली, बद्री (50) पुत्री श्रीराम माली, गीता (22) पत्नी खाना माली, सायरी (40) पत्नी बद्री माली का हॉस्पिटल में उपचार जारी है।

फर्जी जिला स्पेशल टीम के खिलाफ कार्रवाई

ब्यावर, (निर्स) जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह आई.पी.एस. के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र शर्मा व वृत्ताधिकारी राजेश कसाना के निरीक्षण सुपरविजन में सदर थानाधिकारी गंगाराम खावा मय टीम द्वारा जिला स्पेशल टीम के फर्जी सदस्य बन आमजनो को धमकाने एवं लुटपाट करने के प्रयास करने वाले दो आरोपीयो परमेश्वरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावत उम्र 25 साल निवासी ग्राम झाला की चौकी कायाभीला पुलिस थाना बर एवं संदीप डिडवानिया उर्फ संजु जाति रैगर उम्र



लुटपाट करने के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

- फर्जी जिला स्पेशल टीम के सदस्य बन आम जनो को धमकाने एवं लुटपाट के प्रयास में दो आरोपी गिरफ्तार

22 साल निवासी सुधाधनार पुलिस थाना रामगंज अजमेर को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त वाहन बोलरो कैम्पर भी जब्त किया है।

गौरतलब है की 25 नवंबर को आजाद काठान की वायरल खबर के संबंध में तलाब करने पर एक लिखित रिपोर्ट पेश की गई की 23/24 नवंबर को प्रभु की बगीचा में शादी समारोह से निकल कर रात को मेरी स्कूटी से घर आ रहा था तब कारगिल काठान पेड़ोंल पम्प से पहले हाईवे पर एक सफेद कलर की महिन्द्रा कैम्पर से एक आदमी नीचे

स्पेशल टीम के फर्जी सदस्य बन आमजनो को धमकाने एवं लुटपाट करने के प्रयास की वारदात को स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर लिया गया और घटना में प्रयुक्त वाहन बोलरो कैम्पर को जब्त करने में सफलता मिली। गंगाराम खावा सदर थानाधिकारी गंगाराम खावा पुलिस टीम में रामजस सहायक उप निरीक्षक, जितेन्द्र सिंह हैडकानि, महेन्द्र कुमार, राजु कानि, भवानी सिंह कानि, रिशपाल आदि थे।

अनियंत्रित होकर बाइक घुसी ट्रौले में, दोनों की मौत

बाइक और मोबाइल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए

गंगपुर सिटी। जयपुर हाईवे पर बुधवार सुबह बाइक आगे चल रहे ट्रौले में जा चुसी। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर घायल हो गए। सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को गंगपुर सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचाया। जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के आने के बाद पोस्टमॉर्टम करारकर पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

जानकारी के अनुसार बाद गहनौली निवासी मोनू वैष्णव (22) पुत्र पुरुषोत्तम और मनमोहन वैष्णव (20) पुत्र मुरारी लाल दोनों बाइक से गंगपुर सिटी पानी की मोटर का सामान लेने के लिए आ रहे थे। इस दौरान गंगपुर सिटी-जयपुर रोड पर बाइक कला गांव के पास सुबह करीब 9:30 बजे बाइक बेकाबू हो गई और आगे चल रहे ट्रौली से जा टकराई। जिसके कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बाइक और मोबाइल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो

गए। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस 108 ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घटना का पता चलने पर सदर थाना पुलिस गवर्नमेंट अस्पताल पहुंची।

सदर थाने के एसआई दाताराम ने बताया कि घटना के बारे में परिजनों को सूचना दी गई और परिजनों के आने के बाद दोनों का पोस्टमॉर्टम करारकर सब परिजनों के सौंप दिया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, 47 हजार का अर्थदण्ड

कोटा, (निर्स)। नाबालिग से दुष्कर्म के 22 माह पुराने मामले में पाँक्सो कोर्ट क्रम-3 ने आरोपी नर्सिंग स्टूडेंट को दोषी मानते हुये 20 साल की सजा सुनाई साथ ही 47 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया है कि 16 वर्षीय पीडिता से मोबाइल पर फेसबुक के जरिये आरोपी युवक ने दोस्ती बढ़ाई और जनवरी 2023 में युवक ने अपने किराये के कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील विडियो बना लिया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी और पीडिता एक ही गांव के थे जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने उससे संबंध बनाये थे। मामले का पता चलने पर नाबालिग के पिता ने 11 अप्रैल 2023 को महावीर नगर थाने में इसकी शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी नर्सिंग स्टूडेंट को गिरफ्तार किया था। मामले में कोर्ट में 19 गवाह व 42 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

तीन दिसम्बर को सैकड़ों लोग बसों से सुबह 6 बजे साधुवाली लिंक चैनल पहुंचेंगे वहां से एकजुट होकर लुधियाना की ओर कूच करेंगे

गजसिंहपुर, (कासं)। जहर से मुक्ति आंदोलन के तत्वावधान में सिंहसभा गुरुद्वारा में किसान, मजदूर व व्यापारी संगठनों की बैठक संयुक्त बैठक हुई। जहरीले व कैमिकल युक्त पानी की रोकथाम के लिए 3 दिसम्बर को लुधियाना जाने का निर्णय लिया गया। सैकड़ों लोग बसों के माध्यम से सुबह 6 बजे साधुवाली लिंक चैनल पहुंचेंगे वहां से एकजुट होकर लुधियाना की ओर कूच करेंगे।

आंदोलन के संयोजक मनिन्द्र सिंह मान ने कहा पंजाब सरकार ने जहरीले पानी के

उपचार के लिए करोड़ों रूपये की लागत से एसटीपी संयंत्र लगाए हैं लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है। ऐसे जहरीले पानी को किसी भी तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा हमारी मांग स्पष्ट है कि सतलुज में बुझा नाला से प्रवाहित प्रदूषित जल को ट्रीट करके भी नहीं डाला जाना चाहिए। वहीं उन औद्योगिक इकाइयों को बंद करना चाहिए जो सतलुज नदी को प्रदूषित कर रही है।

रविन्द्र तरखान ने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी पंजाब और राजस्थान के

करीब 3 करोड़ लोगों पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराने में सरकारों की नाकामी रही है व नदियों को प्रदूषित होता देख रही है। उन्होंने कहा सतलुज पर आश्रित पूरा क्षेत्र कैसर, काला पीलिया और असाध्य रोगों व केन्द्र बन रहा है। इस मौके पर किसान नेता गुरचरण सिंह मोड़, राकेश शर्मा, नगर पालिका चेयरमैन चमकौर सिंह रामगाढिया, मेघराज खत्री, मजदूर नेता कश्मीरी लाल, हंसराज गोदारा, व्यापारी राम बजाज व नगर पालिका के कुछ पार्षद भी बैठक में शामिल थे।

सिन्धु दर्शन यात्रा के लिए मिलेगी 15 हजार रूपए की आर्थिक सहायता

सिन्धी समाज के लिए राज्य सरकार का तोहफा

अजमेर, (कासं)। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाथी के आठवाह पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सिन्धी समाज को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सिन्धी समाज की सबसे बड़ी और पवित्र मानी जाने वाली लेह-लद्दाख सिन्धु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 15 हजार रूपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सिन्धु दर्शन यात्रा में चार दिन तक लेह-लद्दाख में धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन होते हैं तथा यह यात्रा 18 जून से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होती है।

सिन्धी समाज के तीर्थयात्री हर साल 23 से 26 जून तक लेह-लद्दाख में सिन्धु दर्शन यात्रा पर जाते हैं। यह

- विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाथी ने किया था मुख्यमंत्री से आग्रह
- सिन्धी समाज की सबसे बड़ी और पवित्र यात्रा मानी जाती है सिन्धु दर्शन यात्रा
- लेह-लद्दाख में चार दिन होते हैं आयोजन, 12 दिन चलती है यात्रा

यात्रा 18 जून से जम्मू एवं कुरुक्षेत्र से प्रारम्भ होती है तथा 30 जून को इसका अधिकारिक समापन होता है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाथी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा को ज्ञापन देकर आठवाह किया था कि सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी अन्य तीर्थ यात्राओं की तरह आर्थिक सहायता दी जाए। इस

पर निर्णय करते हुए राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए 15 हजार रूपए प्रति यात्री की आर्थिक सहायता की घोषणा की है।

गौरतलब है कि वर्ष 1997 में भारत रत्न एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सिन्धु दर्शन यात्रा की शुरुआत की थी। प्रतिवर्ष यह यात्रा 23 से 26 जून तक लेह-लद्दाख में

आयोजित की जाती है। इसमें बड़ी संख्या में सिंधी धर्मावलम्बी भाग लेते हैं। वेद, शास्त्र एवं धार्मिक मान्यताओं में सिन्धु नदी का बड़ा महत्व है। लगभग सभी ठाणों में सिन्धु नदी का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रगान में भी सिन्धु नदी का उल्लेख है। सिन्धी समाज में भी ईष्ट देव श्री झुलेलाल जी के अवतार का जल से संबंध है। इसी में यह यात्रा सिन्धी धर्मावलम्बियों के लिए बड़ी पवित्र मानी जाती है। प्रतिवर्ष देश के लगभग 25 राज्यों से सिन्धी धर्मावलम्बी इस पवित्र यात्रा पर जाते हैं। यह यात्रा जम्मू एवं कुरुक्षेत्र से प्रारम्भ होती है एवं लगभग 12 दिन चलती है। यात्रा में लेह-लद्दाख में विशिष्ट धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन होते हैं।

नाथद्वारा में भारत का पहला क्रिकेट स्टेडियम होटल खुलेगा

उदयपुर, (कासं)। भारत का पहला शानदार क्रिकेट स्टेडियम होटल (एमपीएमएससी) राजस्थान के पवित्र शहर नाथद्वारा में 2025 में खुलने जा रहा है। मिराज ग्रुप की तरफ से बनाये जानेवाला यह होटल रेडिसन होटल समूह द्वारा संचालित किया जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होटल है, जिसमें शानदार आवास के साथ लाइव क्रिकेट देखने की सुविधा है। इसमें 234 आलीशान कमरे होंगे। उम्र में से 75 प्रतिशत कमरों में से क्रिकेट मैदान का अनोखा नजारा दिखेगा। यहां उठरने वाले मेहमान अपने कमरे में बैठकर आराम से क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं। यह होटल विलासिता और डिजाइन का सही मिश्रण है। आतिथ्य सत्कार और क्रिकेट के प्रति जुनून, दोनों मामले में यह एक नया मानक स्थापित करता है। इस खेल परिसर में रहकर मदन पालीवाल की दूरदर्शिता और रेडिसन के उत्कृष्ट आतिथ्य का अनुभव लेने के लिए तैयार हो जाएं।

देवमाली में रोप वे बनने की आस जगी, श्रद्धालुओं को राहत

मसूदा, (निर्स)। उपखण्ड क्षेत्र के बेस्ट टूरिज्म विलेज देवमाली में रोप वे बनने की आस जगी है। देवमाली में राज्य की उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी के आगमन पर क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने देवमाली में रोप वे निर्माण करवाने की मांग की थी जिससे देवधाम देवमाली में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके।

इस दृष्टि से जिलाधीश ब्यावर के निर्देश पर उपखण्ड अधिकारी ने विकास अधिकारी, पंचायत समिति मसूदा को पत्र प्रेषित कर टाम देवमाली में भगवान श्री देवनायण मन्दिर में पहुँच मार्ग हेतु रोप-वे निर्माण करवाना जाने हेतु सरपंच, टाम पंचायत देवमाली से समन्वय स्थापित करते हुए स्थल चिह्नित कर, टाम पंचायत अनायात प्रमाण सहित रिपोर्ट अतिश्रीधर भिजवाये जाने के निर्देश जारी किए जाने पर विकास अधिकारी संदेश पारशार ने देवमाली सरपंच एमम टाम विकास अधिकारी

- देवमाली में राज्य की उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी के आगमन पर क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने देवमाली में रोप वे निर्माण करवाने की मांग की थी

को भेज कर टाम देवमाली में भगवान श्री देवनायण मन्दिर में पहुँच मार्ग हेतु रोप-वे निर्माण करवाना जाना हेतु पंचायत समिति मसूदा तकनीकी अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए स्थल निरीक्षण चिह्नित कर टाम पंचायत अनायात प्रमाण पत्र सहित रिपोर्ट कार्यालय को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिलाधीश के देवमाली में रोप वे के लिए स्थान के चिन्हीकरण के बाद देवमाली में रोप वे बनने की आस जगी है।

सोने की चैन लूट का आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निर्स)। महावीर नगर पुलिस ने कार्यवाही करते हुये महिला के गले से सोने की चैन लूटने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। महावीर नगर थानाधिकारी महेन्द्र कुमार मारु ने बताया कि 26 अक्टूबर को फरियादी टीचर कॉलोनी निवासी अविराज विजय ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि मोटरसाइकिल पर दो युवक आये और कोटिल्लय सामुदायिक भवन के समीप मेरी मां के गले से सोने की चैन लूटकर फरार हो गये। थानाधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को तलाश के लिये टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम ने मुसबौर की सूचना पर मामले में कार्यवाही करते हुये तालाब गांव अनंतपुरा निवासी मोहम्मद शहजाद (20) को गिरफ्तार किया।

9वीं से 12वीं की परीक्षा 17 दिसंबर से

बीकानेर, (कासं)। शिक्षा विभाग से जुड़े राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में क्लास 9 से 12 तक अर्द्धवार्षिक परीक्षा 17 दिसम्बर से शुरू होगी जो 27 दिसम्बर तक चलेगी। राज्य में पहली बार एक साथ हो रहे हाफ ईयरली एजाम का टाइम टेबल जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार सर्दी की छुट्टियों 25 दिसम्बर से शुरू नहीं होंगी। सभी स्कूल में प्रैक्टिकल एजाम 12 से 16 दिसम्बर के बीच आयोजित किए जायेंगे। अब तक समान परीक्षा जिला स्तर पर होती थी, जिसके लिए जिले के किसी एक स्कूल को जिम्मा सौंपा जाता था। पेपर भी जिला स्तर पर तैयार होते थे और प्रकाशित होते थे। लेकिन अब पूरे राज्य में एक ही पेपर से एजाम होगा। ऐसे में पेपर प्रिंटिंग का काम भी एक ही फर्म के माध्यम से किया जायेगा।

- प्रैक्टिकल एजाम 12 से 16 दिसम्बर के बीच आयोजित होंगे

आदेश में कहा गया है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्राइवेट स्कूल में पेपर नहीं रखे जायेंगे। ये पेपर सरकारी स्कूल में रहेंगे, जहां से सभी प्राइवेट स्कूल को निर्धारित समय पर प्राप्त करने होंगे। अगर सरकारी स्कूल में भी सुरक्षा पर संदेह है तो संबंधित पुलिस थाने में पेपर रखे जा सकते हैं। हाफ ईयरली एजाम के लिए हर स्टूडेंट से 20 रूपए फीस ली जायेगी। इसके अलावा ईयरली एजाम के लिए भी फीस साथ में ली जा सकेगी। संयुक्त निदेशक ये फीस पूर्व में गठित समान पारोक्षा संचालन समिति के माध्यम से एकत्रित करके पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा के खाते में जमा करवायेंगे।

सजा सुनते ही अभियुक्त कोर्ट से भागा

उदयपुर, (कासं)। दुष्कर्म मामले में दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाने के बाद अभियुक्त कोर्ट कठघरे से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार पीडित भगत सिंह पुत्र हेरम सिंह राठीड निवासी लखावली सुखेर हॉल रीडर पोक्सो कोर्ट में, 2 उदयपुर ने आरोपी लक्ष्मण पुत्र मोहनलाल निवासी सिंघटवाड़ा तालाब फला जावरमाइन्स के खिलाफ कोर्ट कठघरे से फरार होने का प्रकरण मुपालपुरा पुलिस थाने में दर्ज करवाया।

- कोर्ट ने 26 नवंबर को सजा सुनाई थी

जिसमें पीडित ने बताया कि आरोपी को अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में तथा लैगिंग अपराधों बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने 26 नवंबर को सजा सुनाई थी। इस दौरान आरोपी कोर्ट के कठघरे में खड़ा था सजा सुनाने के बाद अपने अधिवक्ता पुष्करलाल मैनारिया से लक्ष्मण बातचीत कर रहा था कि अचानक वह कठघरे से दौड़ कर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

झुंझुनूं में फर्जी पोस्टमार्टम के बाद अब फर्जी एफआईआर

बाल कल्याण समिति ने करवा दिया पोक्सो का फर्जी मुकदमा, नाबालिग ने किया खुलासा

झुंझुनूं, (निर्स)। चूरू के महिला पुलिस थाने में पिछले महीने एक नाबालिग द्वारा झुंझुनूं के एक पत्रकार, एक बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारी, एनजीओ संचालक समेत छह जनों के खिलाफ दर्ज करवाई गई एफआईआर को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है।

दरअसल सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने इस कथित झुंझुनूं निवासी पोक्सो पीडिता को मां को सुपुर्द किए जाने के आदेश दिए थे। जिसके बाद पीडिता ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा था कि उससे बाल कल्याण समिति झुंझुनूं की कार्यवाहक सदस्य शर्मिला पुनियां खाली कागजों पर साइन करवाकर ले गई और उसने किसी प्रकार का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। इससे पहले कथित पोक्सो पीडिता की मां करीब डेढ़ महीने तक बाल कल्याण समिति और अधिकारियों के चक्कर लगाती रही। वह लगातार अपनी बेटी की सुपुर्दगी के लिए गुहार लगाती रही। लेकिन बाल कल्याण समिति ने मां को उसकी बेटी सुपुर्द नहीं की। जिसके बाद हाईकोर्ट की डबल बैच ने मां को तत्काल बेटी

को मां को सुपुर्द करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट में युवा अधिवक्ता नितिन चौमाल व अधिवक्ता कविश दुबे ने पैरवी की। इधर, मामले बिगड़ते तो बाल कल्याण समिति झुंझुनूं की कार्यवाहक सदस्य शर्मिला पुनियां ने एफआईआर दर्ज करवाने के मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। एफसी ने एफआईआर दर्ज करवाई है।

आधार कार्ड में उलटगैरी समिति, एसआईआर पर कुछ नहीं किया :- इस मामले में बाल कल्याण समिति झुंझुनूं की भूमिका इसलिए भी संदिग्ध हो जाती है कि बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष कमला व सदस्य सभी एक ही बात दोहरा रहे हैं कि नाबालिग को मां आधार कार्ड या फिर अपनी पहचान का कोई दस्तावेज नहीं पेश कर रही थी। जबकि स्वयं समिति ने विभागीय अधिकारियों से एसआईआर रिपोर्ट तैयार करवाई। जिसमें ना केवल मां के, बल्कि पड़ोसियों तक से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार की गई। जो सकारात्मक थी। बावजूद इसके बाल कल्याण समिति ने नाबालिग का संरक्षण

- फंसे तो बोले- हमने नहीं एसपी ने करवाया

उसकी मां को नहीं दिया। चूरू एसपी और झुंझुनूं कलेक्टर को लेकर कही बात :- बाल कल्याण समिति झुंझुनूं की कार्यवाहक सदस्य शर्मिला पुनियां ने राजस्थान पत्रिका से बातचीत में कहा कि उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। एसपी चूरू के द्वारा महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इधर, नाबालिग की मां के प्राथना पत्र खारिज करते हुए एक आदेश में बाल कल्याण समिति ने लिखा है कि चूरू एसपी ने झुंझुनूं कलेक्टर के आदेश पर एफआईआर दर्ज करवाई है। इस सवाल पर शर्मिला पुनियां ने कहा कि कलेक्टर झुट भी बोल सकते हैं। हमारे पास कलेक्टर के आदेश है।

पिछले साल भी करवाई थी एफआईआर :- बाल कल्याण समिति झुंझुनूं का कार्यभार संभालने से पहले बाल कल्याण समिति चूरू ने ऐसी की ऐसी एक एफआईआर जुलाई 2023

में भी इन्हीं कथित आरोपियों के खिलाफ करवाई थी। जो पुलिस जांच में झूठी मिली थी। बावजूद इसके अब झुंझुनूं का कार्यभार संभालने के दो दिन में ही इन्हीं अध्यक्ष व सदस्यों ने एक और एफआईआर दर्ज करवा दी। जिसे लेकर अब परिवादी नाबालिग ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले को लेकर जब बाल कल्याण समिति झुंझुनूं की कार्यवाहक अध्यक्ष कमला देवी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमने जो भी किया है वो नियमों के अनुसार कानून के हिसाब से सही किया है सारा काम। बच्ची के हित में ही किया है। वो हमारी बच्ची थी। जो किया है वो वो बच्ची के हित में किया है। यह कहते हुए फोन काट दिया। इसके बाद हमारे संवाददाता द्वारा बार-बार कमला देवी को कॉल किया गया। लेकिन उन्होंने फोन रिसिव नहीं किया।

सदस्य हरफूल ने विभाग की एसआईआर पर उठाए सवाल :- इस मामले में बाल कल्याण समिति झुंझुनूं के सदस्य हरफूल सिंह ने बाल अधिकारिता विभाग की एसआईआर रिपोर्ट पर ही सवाल उठाए। उन्होंने कहा

कि हमने जो कार्रवाई की। वो हमारे दिमाग से नियमानुसार किया है। ना तो हमारा मकसद था कि बच्ची को परेशान करें। उन्होंने कहा कि जब नाबालिग की मां आई थी तो उसके पास ना तो आधार कार्ड था और ना ही राशन कार्ड। जब उनसे मांग तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है हमारे पास। बच्ची ने अब क्या कहा है। उस पर मैं नहीं जाना चाहता। बातचीत में हरफूल सिंह ने बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार की गई एसआईआर रिपोर्ट में ना तो आधार कार्ड आया और ना ही राशन कार्ड। लगातार सवाल से फंसेते हुए मनीराम ने अंत में यही कहा कि मैं फाइल देखकर ही बताऊंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। धन्यवाद। रामावतार मीणा, कलेक्टर, झुंझुनूं ने बताया कि मेरे पास एक पत्र आया था। जो मैंने उसी वक्त वापिस लौटा दिया था। ना ही मैंने कोई आदेश दिए थे और ना ही निर्देश। बाल कल्याण समिति झुंझुनूं ने अपने आदेश में ऐसा लिखा है। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसकी जांच करवाएंगे।

